इश्तेहार 2019

तृणमूल

माँ–माटी–मानुष के लिए

तृणमूल कांग्रेस
जनता के साथ

हम सभी देश के पक्ष में हैं,
मोदी के पक्ष में नहीं,
जनता के हित में
बीजेपी हटाओ,देश बचाओ

निवेदन

मेरी सभी माँ-भाई-बहनों को हम सब की ओर से हार्दिक श्रद्धा, प्रणाम, सलाम, जोहार, शुभकामनाएँ और अभिनन्दन।

बंगाल सहित, अन्य अनेक राज्यों में शुभ नववर्ष आ रहा है, रमज़ान का महीना भी आ रहा है। सभी सम्प्रदायों के लोगों को शुभ नववर्ष की शुभकामनाएं और अग्रिम रमज़ान मुबारक।

मैं श्रद्धा सहित उन सभी का स्मरण करती हूँ जिन्होंने देश व देशवासियों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। वीर शहीद जवानों से लेकर बहुत से आम लोगों ने भी अपने प्राण गंवाए हैं, मैं उन सभी को हम सबकी ओर से हार्दिक श्रद्धा ज्ञापित करती हूँ।

इस घड़ी, पूरा देश एक तात्पर्यपूर्ण समय के समक्ष खड़ा है क्योंकि शीघ्र ही सत्रहवाँ लोकसभा चुनाव, 2019 होने वाला है। इस बार का लोकसभा चुनाव केवल राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में ही नहीं बल्कि भारत के भविष्य निर्माण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भावी पीढ़ी के समक्ष कैसा भारत सामने आएगा, बहुत कुछ इस लोकसभा चुनाव पर निर्भर करता है। इन बातों को इतना ज़ोर देकर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हमने एक बदले हुए भारत को देखा है, और यह बदला रूप सामने आया है शासक दल बीजेपी के सौजन्य से।

वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्ववाली बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी। उन्होंने देश में 'अच्छे दिन' लाने का वादा किया था। लेकिन उनके शासनकाल में हमने क्या देखा?अच्छे दिन तो दूर रहे, देश सर्वनाश की ओर अग्रसर है। भारत सिर्फ एक देश का ही नाम नहीं है। भारत एक विचारधारा, एक जीवनबोध का भी द्योतक है। और यह विचार, जीवनबोध स्थापित हुआ है कतिपय विशिष्टताओं के कारण। लेकिन बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही, उन पारंपरिक विशिष्टताओं को नष्ट कर एक परिवर्तित भारत निर्माण में लगी हुई है।

हमारा देश विश्व का वृहत्तम लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र की मौलिकता भारत के प्राचीन दर्शन और भारत की प्राचीन परंपरा में निहित है। वेदों और उपनिषदों में बहुलवाद को जो स्वीकृति दी गई है, उसी परंपरा को सम्राट अशोक व अकबर द्वारा सुरक्षित रखा गया था।

इसके अलावा पाश्चात्य देशों में, जहाँ उनकी अपनी निजस्वता को बनाए रखने के लिए दूसरों को दूर रखा जाता है, वहीँ भारत में विभिन्नता के बावज़ूद दूसरों को अपनाकर, उनके साथ समन्वय कायम कर, एकता का प्रयास विद्यमान है। अर्थात् किसी को भी पराया न समझ कर, सभी को अपना बना लेना ही भारत का मूलमंत्र है। भारतवर्ष ने हमें अहिंसा की शिक्षा दी है, विभेद व हिंसा नहीं बल्कि भारत के मूल में हमेशा ही समाज के लिए मंगल तथा विश्व मानवता के लिए मंगल की भावना रही है। इसी भारतवर्ष में बढ़ू चंडीदास ने उद्घोष किया था, सबसे बड़ा सत्य मनुष्य है, उससे ऊपर कुछ नहीं। इसी भारतवर्ष में भेदभाव से ऊपर उठकर, कबीर ने मानवता का जयगान गाया था। इसी भारतवर्ष में, लालन ने मानव साधना की बात कही। यही सन्देश हमें मिलता है रामकृष्ण-विवेकानंद की वाणी में। महात्मा गाँधी ने भी धार्मिक विभाजन के बजाय, धार्मिक समन्वय व शांतिपूर्वक सह अवस्थान वाले भारतवर्ष का स्वप्न देखा था। अतएव प्राचीन काल से ही भारत की इस पुण्यभूमि ने विविधता को साथ लेकर जय गान गाया है मनुष्य का और मानवता का। विविधता में एकता और समन्वय साधन ही भारत की आत्मा का मूलमंत्र है। भारत को समझने के लिए यहाँ की विविधता और बहुलवाद को समझना होगा। लेकिन बीजेपी के पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में हमने यह देखा कि भारत की 'अनेकता में एकता' की इस विशिष्टता को लगातार खतरा झेलना पड़ रहा है। बीजेपी के शासनकाल में हमने देखा कि भारत की इस अनन्य विशिष्टता को मिटाकर, एक संकीर्ण भारत के

निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ विरोधी मतामत का कोई स्थान नहीं है। शासक की बातों से सभी को एकमत होना होगा अन्यथा उस पर शासक दल का आक्रमण, राष्ट्र शक्ति का आक्रमण शुरू हो जायेगा। शासक ने इस महान देश को सृजन के बजाय विध्वंस की ओर धकेल दिया है। भारत को एक अंधकारमय भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। देश का कोई भी शुभ बुद्धि-संपन्न व्यक्ति आज वर्तमान भारत को लेकर चिंतित व शंकित है। भारतवर्ष की विरासत व गौरव की रक्षा करने के लिए, हमें रोकना होगा बीजेपी को। इसी कारण, अगला लोकसभा चुनाव सभी शुभ बुद्धि-संपन्न व्यक्तियों के लिए भारत के गौरव की रक्षा करने की भी परीक्षा है।

बहुलवादी हमारे भारत ने, पूरे विश्व से अपनी धर्मनिरपेक्षता के कारण सम्मान अर्जित किया है। यह धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की अन्यतम विशिष्टता है। और इसी धर्मनिरपेक्षता की धारा वेद-उपनिषद से शुरू कर सम्राट अशोक, अकबर की विचारधारा में छुपी हुई है। धर्मनिरपेक्षता भारत की परंपरा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 'जितने मत, उतने पथ' की विचारधारा वाले इस भारत में विभिन्न वर्गों के लोग प्रेमभाव के उदाहरण को स्थापित कर साथ-साथ रहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना की पताका को उद्दोलित कर, आधुनिक विश्व के समक्ष मानवता की वार्ता को रवीन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, महात्मा गाँधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, डा. अम्बेडकर, एनी बेसेंट जैसे महान व्यक्तियों ने पहुँचाया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर जवाहरलाल नेहरू ने इसी प्रेमभाव व धर्मनिरपेक्षता की पताका को और ऊंचा किया। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में अहिंसा, प्रेमभाव व धर्मनिरपेक्षता का भारत क्रमशः बदलकर हिंसा, दंगे व धार्मिक कट्टरता का मुक्तक्षेत्र बन चुका है। साम्प्रदायिक विषैली हवा फैलाकर, भारत की इस बहुलवाद आत्मा को नष्ट करने जैसे घृणित षड्यंत्र में जुटा है शासक और उसके सहयोगी दल। वे विभिन्न धर्मों, सांस्कृतिक विविधताओं को नकारने के षड्यंत्र में लिप्त हैं। वे उदार भारत की धर्मनिरपेक्ष विशिष्टता को नष्ट कर, उसे एक संकीर्ण देश के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ राष्ट्र की बागडोर होगी कट्टरपंथियों के हाथ में।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के शासनकाल में, नई शक्ति मिली है भारत को घेरे रखने वाली कट्टरपंथी साम्प्रदायिक शक्ति के षड्यंत्र को। यदि वे सफल

होते हैं, तो भारत अपने धर्मनिरपेक्ष, उदार, बहुलवादी विशिष्टताओं को खोकर एक संकीर्ण, निरंकुश, साम्प्रदायिक राष्ट्र के रूप में परिणत होगा। और इसी कारण ये विभेदकारी शक्तियां गांधीजी के अहिंसावादी भारत में साम्प्रदायिक हिंसा व रक्त रंजित दंगे लेकर आई हैं। नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में, पूरे देश में बी जे पी और उनके सहयोगी दल एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जहाँ सब कुछ निर्धारित होगा उनके बताये गए तरीके से। वे ही देशप्रेम का असली अर्थ बताएँगे, वे ही चिन्हित करेंगे कौन देशद्रोही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि स्वाधीनता संग्राम से शुरू कर, देश की राष्ट्रीय पताका या संविधान, इनमें से किसी पर भी इन कट्टरवादियों की आस्था नहीं थी। लेकिन बीजेपी के शासनकाल के दौरान, पूरे देश में विभेदकारी सांप्रदायिक शक्तियों ने अपना फन उठाया है। बहुलवादी भारत के महान आदर्शों को कालिमामय कर, वे कट्टरवाद और सांप्रदायिकता की विषैली वायु को फैला देना चाहते हैं। गांधीजी के अहिंसावादी इस भारत में वे विद्वेष, घृणा व हिंसा के काले बादल लाना चाहते हैं।

वर्ष 2017 के नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। वहां यह स्पष्ट है कि 2010-2017 के बीच पशु हत्या से जुड़े किसी व्यक्ति पर जितने भी उन्मत्त जनता के आक्रमण हुए हैं, उसका 97% पिछले तीन वर्षों में हुए हैं, जिनसे 63 ऐसी घटनाओं में से 61 घटनाओं से गो रक्षक वाहिनी जुड़ी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्मत्त जनता के हाथों खून करने का जो नया झोंक लोगों में बढ़ गया है, वह सबसे ज्यादा परिलक्षित हो रहा है नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के आने के बाद। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इन घटनाओं में से ज्यादातर घटनाएँ बीजेपी सरकार वाले राज्यों में घटी हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी क्षेत्रों में अपराधियों को कट्टरवादियों द्वारा 'वीरों' का सम्मान मिला है। मेरे लिए, ये नृशंस घटनाएँ जितनी भयानक हैं उससे भी ज्यादा भयावह है इन लोगों को 'नायक' का सम्मान मिलने का विषय। इससे स्पष्ट है कि हमारे इस धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु भारत को बीजेपी और उनके दल धर्मान्धता, घृणा एवं विद्वेष के अंधकार की ओर ले जाना चाहते हैं।

पिछले 5 वर्षों के बीजेपी शासन काल में हमने देखा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में ही लोकतंत्र विपन्न हुआ है। हमने यह भी देखा है कि

लोकतंत्र की आड़ में कायम हुई है अघोषित स्वेछाचारिता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने आत्मदंभ के अंधेपन में देश के लोगों पर अपने स्वेच्छाचारी निर्णय लाद दिए हैं। लोकतंत्र में विरोधियों का सुझाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन विरोधियों के सुझावों की उपेक्षा कर, नरेन्द्र मोदी ने देश पर अपने निजी निर्णयों को थोप दिया है। उनके हठकारितापूर्ण निर्णयों से, इस देश के असंख्य गरीब लोग सड़कों पर आ गए हैं। एक तरफ मोदी के नोटबंदी या विमुद्रीकरण तथा इसके साथ ही जल्दबाजी में जी एस टी को लागू करने के निर्णय ने देश की अर्थनीति को पंगु कर दिया है। 8 नवम्बर, 2016 का दिन भारत के इतिहास का एक काला दिन था क्योंकि पूरे देश को अवाक कर, उस दिन नोटबंदी के नाम में 500 और 1000 रुपये के नोटों को निरस्त करने की घोषणा की थी मोदी ने। फलस्वरूप देश की लगभग 86%प्रचलित मुद्रा, उनके एक भाषण से निरस्त हो गई थी। अचानक लिए गए इस अजब निर्णय से पूरे देश के लोग चरम दुर्दशा में पड़ गए। बैंकों के सामने लम्बी लाइनें, लोगों के दैनिक व्यस्त जीवन का एक बड़ा हिस्सा बैंकों की लाइनों में चला गया। वृद्ध, अस्वस्थ लोग भी उस समय घंटों लाइनों में खड़े रहते थे। लाइनों में खड़े रहने और धक्कों के कारण देश में कई असहाय लोगों की मृत्यु भी हुई थी।

इस हठकारितापूर्ण निर्णय का असहनीय परिणाम भुगतना पड़ा था देश के मेहनतकश लोगों और दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों व आम लोगों को। लघु व्यवसायियों से लेकर सीमांत कृषकों, श्रमिकों सभी की रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ा था नरेन्द्र मोदी के इस निर्णय से। नकदी के अभाव में लघु व्यवसाइयों को कच्चा माल खरीदने में वास्तव में बहुत परेशानी हुई थी। क्रेताओं के हाथ में भी नकद का अभाव था, जिसके कारण विक्रेता अपना माल नहीं बेच पा रहे थे। दूसरी ओर, कर्मचारियों को वेतन देने में भी असुविधा हो रही थी। यही बात सीमांत कृषकों पर भी लागू थी। नकद के अभाव में वे भी फसल के लिए खाद और बीज नहीं खरीद पा रहे थे, न ही उन्हें पर्याप्त क्रेता मिल रहे थे। नकद के अभाव में दिहाड़ी मजदूरों को उनकी दैनिक मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, कई श्रमिक बेरोजगार हो गए। नोटबंदी के निर्णय के बाद, रुपये निकालने व जमा करने के नियमों को भी रिजर्व बैंक ने बार-बार बदला। नोटबंदी के पहले 50 दिनों में, 74 विज्ञप्तियां रिजर्व बैंक को जारी करनी पड़ी थीं। पूरे देश में ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि लोग सवेरे से ही इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि अब रिजर्व बैंक कौन सा नया नियम ला रहा

है। भारत के इतिहास में ऐसी दैनिक अनिश्चयता की स्थिति इससे पहले कभी नहीं आई। नरेन्द्र मोदी द्वारा लिए गए इस स्वेच्छाचारी निर्णय के साथ-साथ ही उतर आए थे अनिश्चयता के काले बादल। नोटबंदी की घोषणा के संग-संग ही, मैंने ट्विटर पर इसे प्रमुख आपदा के रूप में उल्लेख किया था। मेरी यह धारणा कितनी सटीक थी, यह आज सभी देशवासियों के सामने प्रमाणित है। क्योंकि जिन कारणों को दर्शा कर नरेन्द्र मोदी ने नोटबन्दी का निर्णय लिया था उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में इस निर्णय के पीछे तीन प्रमुख कारणों की बात कही थी। प्रथमतः देश से काले धन को निःचिन्ह करना, द्वितीयतः नकली नोटों को रोकना एवं तृतीयतः आतंकवादियों को रुपये की आपूर्ति बंद करना जिससे उनकी गतिविधियों पर रोक लगेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पता चल गया कि उनका नोटबंदी का निर्णय हर क्षेत्र में असफल रहा। नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि नोटबंदी के फलस्वरूप, देश काले धन से मुक्त होगा। इसी कारण लोगों ने देश की भलाई के लिए, बैंक के सामने लम्बे समय तक खड़े रहने के झंझट को भी मान लिया था। लेकिन धीरे-धीरे पता चल गया कि नोटबंदी देश को काले धन से मुक्त करने में पूरी तरह विफल रही। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के 2017-18 आर्थिक वर्ष की रिपोर्ट से पता चलता है कि जितना धन निकाला गया था उसका 99.3% ही वापस बैंक में आ गया है। अतएव पूरे देशवासियों को असीम कष्टदायक परिस्थिति में डालकर, 100 से ज्यादा लोगों के शवों पर खड़े होकर नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को असफलता के सिवा कोई उपहार नहीं दिया। नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि नोटबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध है। लेकिन रिजर्व बैंक का हिसाब देखने पर लगता है कि नोटबंदी की घटना ही एक बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री के इस तुगलकी निर्णय से करोड़ों कृषक, मजदूर, असंगठित कर्मचारियों को भी अत्यंत परेशानी झेलनी पड़ी थी।

नरेन्द्र मोदी ने अपने चुनावी प्रचार तथा नोटबंदी के समय भी काले धन व भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा बात की थी। बड़े ही दंभ पूर्ण तरीके से उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया था कि वे देश को भ्रष्टाचारमुक्त करेंगे, पूरा काला धन वापस लाएंगे। विदेशों में रखा काला धन भी वे देश में वापस लाएंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या दिखी?काले धन की वापसी की कोई बड़ी खबर किसी संवाद माध्यम को अभी तक नहीं मिली, उलटे भ्रष्टाचार और बढ़ा है, और तो और इस भ्रष्टाचार को शासक दल ने ही छुपाया है।

नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि नोटबंदी के जरिये आतंकवादी गतिविधियों को निर्मूल किया जा सकेगा। लेकिन यह बात भी सर्वथा गलत साबित हुई। नोटबंदी के बाद, कश्मीर और ज्यादा अशांत हो गया है। आतंकवादियों द्वारा, एक के बाद एक, हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी ओर छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों में भी, माओवादी क्रियाकलाप बंद नहीं हुए। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के ज़माने में, भारत में आतंकवाद में 260 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अर्थात्, नोटबंदी को लेकर मोदी और बीजेपी द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी की सफलता के बारे में वे जो दावे कर रहे हैं वे भी असत्य हैं। अतएव, नोटबंदी ने देश का कोई भला तो किया ही नहीं, उलटे इसके कारण गरीब लोगों के जीवन में अवर्णनीय परेशानी हो गई थी। चूँकि लगभग पूरा पैसा ही बैंक में वापस आ गया था, इसी कारण बैंक सावधि जमा पर ब्याज कम करने को बाध्य हुए थे। ब्याज कम हुआ है अल्प बचत योजनाओं का भी। इसी कारण, देश के वरिष्ठ नागरिक तथा बैंक की ब्याज पर निर्भर व्यक्तियों को भी चरम परेशानी झेलनी पड़ी थी।

सिर्फ़ नोटबंदी का ही प्रहार नहीं हुआ, उसके संगी के रूप में हाजिर हुआ था जी एस टी भी। हमने हमेशा कहा कि हम सटीक रूप से क्रियान्वित जी एस टी के पक्ष में हैं। देश के लिए ग्रहण किये गए इतने बड़े प्रस्ताव से पूर्व हमें देखना चाहिए कि हमारे देश की अर्थनीति इस कर व्यवस्था के लिए प्रस्तुत है कि नहीं। इसी कारण, हम जल्दबाजी में जी एस टी लागू करने के खिलाफ थे। इस बात से हमने बार बार केंद्र को भी अवगत कराया था। लेकिन हमारे देश का जो संयुक्त राष्ट्रीय ढांचा है, उसे स्वेच्छाचारी नरेन्द्र मोदी की सरकार महत्व न देकर, अपने निर्णय को थोपने के लिए तत्पर हो गई। जी एस टी के क्षेत्र में भी ठीक यही हुआ। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा हमारे देश के समस्त छोटे, मझोले उद्योगों से जुड़े कर्मचारियों को, छोटे व्यवसायियों और कृषकों को। गरीब लोगों की रोजी-रोटी विपन्न कर, नरेन्द्र मोदी ने इतिहास में अपना नाम लिखाया है। इसी कारण मेरे लिए जी एस टी का अर्थ है 'ग्रेट सेल्फिश टेक्स'। जो टेक्स मोदी आम लोगों को परेशान करने के लिए, रोजगार छीन लेने के लिए, व्यवसाय को बंद करने के लिए, आर्थिक नीति को ध्वस्त करने के लिए लाये हैं। किसी एक मध्य रात्रि को भारत को ब्रिटिशों से स्वाधीनता मिली

थी। और पुनः किसी एक मध्य रात्रि को, देश के गरीब लोगों को मिली आर्थिक पराधीनता, मोदी के दिए जी एस टी के कारण।

सत्ता में आने के बाद ही, उन्होंने ढोल पीटकर 'मेक इन इंडिया' की घोषणा की थी। इस परियोजना के जरिये, विदेशों से काफी निवेश आएगा इस बात का भी वादा किया। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी के शासनकाल में निवेश लगातार कम हो रहा है। मोदी के शासनकाल में रुपया मूल्य के पतन से पीड़ित है। पेट्रोल-डीजल, दोनों ही शतक मारने की दिशा में दौड़ रहे हैं। घरेलू गैस की कीमतें गगनचुंबी हो गयी हैं। पूरे देश में बेरोजगारी है। जो परिस्थितियां बन रहीं हैं, मोदी देश को दिवालिया करने की दिशा में ले जा रहे हैं। और उस पर से नोटबंदी और जल्दबाजी में जी एस टी लागू करने जैसे हठकरितापूर्ण निर्णय से गरीब लोगों की चरम दुर्दशा हुई है। नरेन्द्र मोदी ने एक ऐसी अर्थनीति शुरू की है जिसका अर्थ गरीबों को और दुर्दशा की ओर ढकेलना है। इस आर्थिक दुर्दशा, लगातार पिछड़ेपन को छुपाने के लिए बीजेपी, लोगों के मन में धर्म की राजनीति, मंदिर-मस्जिद की राजनीति, विद्वेष की राजनीति को प्रवेश कराना चाहती है। जहाँ धर्म के मोह में अंधे होकर लोग अपनी ओर देखना, अपने विकास की ओर देखना भी भूल जाएँगे। वे नरेन्द्र मोदी और बीजेपी द्वारा उनके विकास के लिए किये गए वादों को भी भूल जाएँगे। लेकिन हमारी आस्था लोगों पर है। मेरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में लोग अपने वोट के द्वारा बीजेपी सरकार द्वारा की गई प्रतारणाओं का सटीक जवाब देंगे।

भारत के ज्यादातर लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। इसलिए देश का विकास, मूलतः कृषकों के विकास पर ही निर्भर है। बीजेपी शासनकाल में कृषक ही चरम दुर्दशा के शिकार हैं। एक तरफ तो वे ऋण के बोझ से जर्जर हैं, तो दूसरी ओर उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इस सरकार के समय में देश का कृषि ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। देश की कृषि अर्थनीति, इस सरकार के समय में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस सरकार के समय में ही कृषि की वृद्धि में कमी आई है। वर्तमान में यह वृद्धि 2 प्रतिशत से भी कम है, जो पिछले तीन दशकों में सबसे कम है। पिछले पांच वर्षों में कृषकों की वास्तविक आय (रियल इनकम) प्रतिवर्ष1.3 प्रतिशत घटी है। फसल का उचित मूल्य न मिलने के कारण एवं ऋण के बोझ के कारण, देश के कृषक प्रतिवर्ष आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं।

इसी बीच, केंद्र ने वर्ष 2017 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वर्ष 2013 से देश में प्रतिवर्ष 10, 000 से ज्यादा कृषक आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब अपने को कृषक हितैषी बता कर प्रचार कर रहे हैं, उसी समय बीजेपी शासित महाराष्ट्र में कृषकों के दुर्दशा की छवि स्पष्ट रूप से सामने आई। स्वयं महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 मार्च 2018 से 31 मई तक वहां 639 कृषक आत्महत्या की घटनाएं घटी। मोदी सरकार के शासनकाल में एक ओर जहाँ कृषि उत्पादन में कमी आई है, तो दूसरी ओर कृषक आत्महत्या की घटनाएँ 42 प्रतिशत बढ़ी हैं।

लेकिन कृषकों की आत्महत्या की घटनाओं को बंद करने के लिए जब उनको ऋण से मुक्ति देने की बात आती है, तब बीजेपी सरकार के वित्त मंत्री अपने दायित्व की उपेक्षा करते हैं। कृषकों के क्षोभ के कारण जब कोई राज्य ऋण माफ़ी का निर्णय लेता है, तब केन्द्रीय वित्त मंत्री खुले रूप से कहते हैं कि यह दायित्व राज्य की सरकार का ही है एवं ऋण माफ़ी का कोष भी उस राज्य को जुटाना पड़ेगा। केंद्र सरकार यह कोष नहीं देगी। असल में कृषकों की समस्याओं से, केंद्र सरकार सर्वदा पल्ला झाड़ देती है मानो देश के कृषकों का हित, आत्महत्या रोकने के प्रयास का कोई दायित्व केंद्र सरकार का नहीं है। कृषकों की ऋण माफ़ी का कोई सकारात्मक निर्णय न लेने के साथ साथ, बी जे पी सरकार की कॉर्पोरेट धन कुबेरों के लिए चिंता का कोई अंत नहीं है। इनके द्वारा करोड़ों रुपये के ऋण लेकर न चुकाने पर भी केंद्र उनका ऋण माफ़ कर रही है, अन्यथा उन्हें निर्विघ्न विदेशों में भागने में सहयोग कर रही है। यह आश्चर्य की बात है, जिस देश में सामान्य ऋण के कारण प्रतिदिन कृषक आत्महत्या करने को मजबूर हैं उसी देश में सरकार कॉर्पोरेट धन कुबेरों के करोड़ों रुपये के ऋण को माफ़ कर रही है। 2017 के सितम्बर तक, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगभग 2 लाख 42 हजार करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं। संसद में यह जानकारी बी जे पी सरकार के वित्त मंत्रालय ने स्वयं दी है। बैंकों ने इस बात को मान लिया है कि इस विशाल परिमाण के ऋण को चुकाया नहीं जायेगा। लेकिन किससे कितना अर्थ देय है अथवा किनके ऋणों को बैंक के हिसाब खातों से हटाना पड़ा है-संसद में वित्त मंत्रालय इस बात की जानकारी देने के लिए राजी नहीं हुआ। 'कानून के हिसाब से ये आंकड़े गोपनीय हैं', तर्क की आड़ ली गई। इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि उस ऋण का बड़ा अंश ही कॉर्पोरेट धन कुबेरों द्वारा लिया

गया ऋण है। और बी जे पी सरकार उनके प्रति उदार होने के कारण, ऋण अदायगी में उनकी कोई तत्परता नहीं है।

बी जे पी सरकार पूरी तरह से झूठ पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह वादा किया था कि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी कर के दिखाएंगे। लेकिन उनके शासनकाल में कृषकों की दुर्दशा कई गुना बढ़ी है। कृषि के क्षेत्र में मोदी की तीन फ्लैगशिप योजनाओं की स्थिति भी एक जैसी ही है।

बी जे पी के शासनकाल में कृषकों की इस दुर्दशा के कारण ही हमने एक के बाद एक, उनके असंतोष को देखा है। उनके शासनकाल में कृषकों की चरम दुर्दशा हुई है, ये आंकड़ों से ही स्पष्ट है। एन सी आर बी के आंकड़ों से ही पता चलता है कि वर्ष 2014 में पूरे देश में कुल 640 विरोध विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किये गए थे। वर्ष 2016 में, ये बढ़कर 4800 कार्यक्रम हो गए। वर्ष 2018 में, इसमें कई गुना वृद्धि हुई। हमने इसी बीच देखा कि बी जे पी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में कृषकों की गोली मार कर हत्या की गई। महाराष्ट्र की बी जे पी सरकार द्वारा भी कृषकों को प्रताड़ित किया गया। असल में, बी जे पी गरीबों की उन्नति की बात करके सरकार में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने गरीबों की ही उपेक्षा की और विकास किया है कॉर्पोरेट धन कुबेरों का।

नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में देश एक विभीषिकामय दौर से गुजर रहा है। देश के स्वायत्त शासित, स्वाधीन संस्थाओं को बी जे पी ने अपने आज्ञाकारी दास के रूप में परिणत किया है। इन संस्थाओं को बी जे पी ने अपने राजनैतिक निहित स्वार्थ के लिए काम में लगाया है। लोकतांत्रिक ढांचे में विरोधी दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार के विरोध का अधिकार, भिन्न मत व्यक्त करने की स्वाधीनता संसदीय लोकतंत्र का आधार है। दूसरी ओर, सी बी आई से लेकर आर बी आई जैसी देश की स्वायत्तशासित, स्वाधीन संस्थाएं भी लोकतंत्र की स्तम्भ हैं। लेकिन नरेन्द्र मोदी शासित बी जे पी सरकार के शासनकाल में ये दोनों ही ध्वस्त होने की कगार पर हैं। एक तरफ नरेन्द्र मोदी लोकतंत्र को विपन्न कर देश को अपने निरंकुश शासन के रूप में परिणत कर रहे हैं जहाँ शासक जो भी कहेंगे, उसे देश की जनता को सर झुका कर मानना पड़ेगा। विरोधी दलों के विरोध को रोकने के लिए उनकी आवाज को दबा देना, वर्तमान में एक सामान्य सी बात हो गई है। फलस्वरूप, इस

सरकार के शासनकाल में विरोधियों के स्वर पर प्रश्न उठाया जा रहा है एवं लोकतंत्र में अलग मत प्रकाश करने का आधार भी विपन्न हो रहा है।

पूरे देश में केन्द्रीय संस्थाओं की तत्परता देखने से लगेगा कि इस सरकार ने मानो भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। लेकिन गंभीरता से देखने पर समझ में आएगा कि इन संस्थाओं को बी जे पी अपने विरोधियों को डराने के लिए राजनैतिक हथियार के रूप में काम में लगाने में ही ज्यादा इच्छुक है। लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि ये संस्थाएं उन्हीं राज्यों में ज्यादा तत्पर हैं जहाँ बी जे पी विरोधियों की सरकार चल रही है। साथ ही बी जे पी नेताओं के खिलाफ उठी शिकायतों की जांच करने में केन्द्रीय संस्थाओं की हिरण्मय नीरवता व अनिच्छा हमें आश्चर्यचकित कर देती है।

हमने देखा है कि असम में नागरिक पंजी के नाम में लाखों वैध नागरिकों को अनुसूची से हटा दिया गया है। समाचार पत्रों के अनुसार 23 लाख हिन्दू बंगाली, बंगाली मुसलमान, स्थानीय असमिया, नेपाली, बिहार, उत्तरप्रदेश व तमिलनाडु के वास्तविक वोटरों का नाम लिस्ट में नहीं है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी। मैंने अपने दल के 8 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल को वहां की स्थिति का आंकलन करने भेजा था। लेकिन हमारे प्रतिनिधि मंडल को बी जे पी सरकार ने हवाई अड्डे पर ही रोक दिया। प्रतिनिधि मंडल की महिला सदस्यों को भी अपमानित किया गया। बाद में, नागरिक पंजी को लेकर सारे उत्तर पूर्वी राज्य उत्ताल हो गए। बी जे पी शासनकाल में पूरे देश में अराजकता फ़ैल गई है।

अपने शासनकाल में, बी जे पी देश के नागरिकों के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करने में तत्पर थी। सभी लोगों की गतिविधियों पर नजर रख कर लोगों को भयभीत करना चाहती है जिससे लोग उनका विरोध करने से पहले दस बार सोचें। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने ट्विटर, व्हाट्स एप, फेसबुक पर नजर रखने के लिए सूचना व सम्प्रचार मंत्रालय के एक सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब बनाने की योजना बनाई थी। वे एक ऐसी प्रोद्योगिकी बनाना चाहते हैं जो पूरे डिजिटल जगत पर नज़र रखेगी। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्स एप पर लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के जरिये वे सूचनाएं एकत्र करेंगे। इतना ही नहीं, केंद्र की इस परियोजना में नागरिकों के इ-मेल से भी सूचनाएं इकट्ठा करने की अनुमति मिलेगी उन्हें। अपनी इच्छानुसार, वे किसी भी फेसबुक या ट्विटर अकाउंट पर नजर रख सकेंगे। इसके साथ साथ,

विरोधी दल शासक की क्या आलोचनाएँ कर रहे हैं और वे आम जनता को कितना प्रभावित कर रही हैं, इसकी जानकारी भी वे इस निगरानी से प्राप्त कर सकेंगे।

सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नागरिकों के संविधानिक अधिकारों पर अवांछित हस्तक्षेप कर के ही, वे यह नजरदारी करना चाह रहे थे। व्यक्तिगत स्वाधीनता का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत है। लेकिन शासक इस मौलिक अधिकार की परवाह न कर, देश में शुरू करना चाहते थे निगरानी की यह व्यवस्था। और शासक की इस व्यवस्था का हम लोगों ने तीव्र विरोध किया था। हमारे दल की ओर से ही सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज़ किया गया था। हमने कहा कि सरकार सोशल साईट पर नागरिकों की गोपनीयता को विघ्नित करना चाहती है तथा इसके कारण सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। और हमारे द्वारा दर्ज़ किए इस मामले के कारण, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अंततः पीछे हटना पड़ा।

नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर केंद्र के हस्तक्षेप की यह प्रवृत्ति खुले रूप में वर्ष 2018 के दिसम्बर में केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देशिका से स्पष्ट हो गई। इस निर्देशिका के अनुसार, सूचना प्रोद्योगिकी कानून 69-1 के तहत, देश में सर्वत्र किसी भी कंप्यूटर पर देश की 10 केन्द्रीय संस्थाएं नजर रख सकती हैं। इस नए निर्देश के आधार पर, देश की 10 केन्द्रीय संस्थाएं केवल इ-मेल पर ही नहीं बल्कि किसी के भी कंप्यूटर या फोन में रखी गई सूचनाओं, फोटो पर नजर रख सकती हैं। इतना ही नहीं, इस निर्देशिका में यह भी कहा गया है कि यदि किसी की व्यक्तिगत सूचनाओं पर भी किसी प्रकार का संदेह होता है, तो ये संस्थाएं उसके फ़ोन या कंप्यूटर को जब्त कर सकती हैं। सम्बंधित मोबाइल या कंप्यूटर मालिक से पूछताछ भी की जा सकती है। और यदि वे जांच संस्थाओं के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें सात साल की जेल भी हो सकती है।

प्रश्न यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में, कोई भी सरकार इस तरह से नागरिकों पर नजर रख सकती है क्या?देश की शीर्ष अदालत ने ही संविधान की 21 धारा के तहत गोपनीयता के अधिकार को स्वीकृति दी है। लेकिन सरकार यदि इस तरह से नजर रखती है, तो नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गये गोपनीयता के अधिकारों का लंघन

होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यदि इस नजरदारी की बात कही जाए, तो वे अधिकार तो केंद्र सरकार के पास पहले से ही है। इस के लिए, सरकार के पास एक से ज्यादा मशीनरी भी है। लेकिन यदि नई निर्देशिका कार्यकारी हो जाती है, तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत क्षेत्र में भी राष्ट्र व शासक दल हस्तक्षेप कर सकता है। नागरिकों की किसी भी स्वाधीनता या गोपनीयता को बी जे पी सरकार स्वीकृति देना नहीं चाहती। पूरे देश में बी जे पी मानो एक अघोषित सुपर इमरजेंसी लाई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि अगर वे सत्ता में आते हैं, तो कश्मीर शांत हो जाएगा। कोई भी आतंकवादी भारत में आतंक फ़ैलाने का साहस नहीं दिखा पायेगा। लेकिन हमने देखा कि बी जे पी सरकार आने के बाद कश्मीर और ज्यादा अशांत हो गया है। एक के बाद एक हुए आतंकवादी हमलों में हमारे सेना जवानों के प्राण गए हैं। हाल ही में, पुलवामा में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में 40 से ज्यादा वीर जवानों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि इस हमले की जानकारी खुफिया विभाग को पहले से होने के बावजूद हमले को रोका न जा सका, हमारी सेना को बचाया न जा सका। मेरे मन में तो यह प्रश्न जाग रहा है कि वोट से पूर्व सभी असफलताओं से लोगों की नजर हटाने के लिए, कहीं यह बी जे पी का राजनैतिक गेम प्लान तो नहीं है?

पिछले पांच वर्षों से भारत में, बी जे पी शासन का इतिहास असल में लोगों को प्रताड़ित करने का इतिहास है। इस दौरान, हमने लोगों के जीवन की चरम दुर्दशा को देखा है। और इस सरकार के शासनकाल में, भारत भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का स्वर्ग बन चुका है। सभी केन्द्रीय संस्थाओं में प्रभावशाली पदों पर बी जे पी के घनिष्ठ व्यक्तियों को बिठाया जा रहा है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर भी बी जे पी के स्नेहिल व्यक्तियों को आसीन किया जा रहा है। इस शासनकाल में हमने देखा है शिक्षा के क्षेत्र में एक के बाद एक राष्ट्रीय हस्तक्षेप। इस शासनकाल में यदि किसी बुद्धिजीवी ने विरोध किया, तो उसे उसके पद से हटाने का षड्यंत्र रचा गया। बी जे पी के विभिन्न मित्र कॉर्पोरेट धन कुबेरों को कानून बहिर्भूत विभिन्न सुविधाएँ दी गईं । उन्हें बैंकों से करोड़ों रुपये दिलवाने की व्यवस्था की गई। यदि वे उस ऋण को न चुका पाएं, तो सरकार उन्हें निर्विघ्न रूप से देश को छोड़ कर भागने की भी व्यवस्था कर रही है।

शासक बी जे पी, देश में देशप्रेम के नाम पर उग्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यदि कोई उग्रवाद के खिलाफ बोलता है तो उसे देशद्रोही चिन्हित कर दिया जाता है। ये सब कुछ हमने इसी शासनकाल में देखा है। मोदी तथा बी जे पी ने एक ऐसी धारणा बनाई है जहाँ उनकी ही विचारधारा एकमात्र देश के लिए मंगलकारी है, और उस विचारधारा से सहमत न होने पर देशद्रोही का इल्जाम लगा कर उस पर सब टूट पड़ते हैं। 'हीरक राजार देशे' में हमने देखा है कि वहां प्रजा को प्रश्न करने का ही अधिकार नहीं था। नरेन्द्र मोदी के ज़माने में भी हमने देखा है कि भारत में भी 'हीरक राजार देशे' की छाया उतर आई है। लेकिन आज जो बी जे पी देश में देशप्रेम का प्रमाणपत्र बाँट रही है, उसी बी जे पी के पितृ संगठन की भूमिका भारत के स्वाधीनता संग्राम में घृणित भूमिका थी। जो भारत की स्वाधीनता के विरोध में थे, आज वे ही देशप्रेम के ठेकेदार बने हैं। वे पूरे देश में मानवता को कुचलकर, भ्रांत देशप्रेम का मोह फैला रहे हैं। इससे किसी को भी 'देशद्रोही' का नाम लगाकर, उस पर आक्रमण किया जा सकता है।

मोदी सरकार के शासनकाल में हमने मानवाधिकारों की चरम विपन्नता देखी है। नरेन्द्र मोदी ने 'स्वच्छ भारत' की बात कही थी। लेकिन वास्तविक अर्थों में, पूरे विश्व के सामने बिल्कुल स्वच्छ रूप से स्पष्ट है कि भारत उनके शासनकाल में उन्मत्त जल्लादों का मुक्त क्षेत्र बन चुका था। उनका नारा था 'सब का साथ, सब का विकास'। लेकिन पिछले पांच वर्षों में इस नारे का देश में अलग अर्थ ही था। एक के बाद एक मुस्लिमों का खून, दलितों के रक्त से भीगे हुए इस देश में 'सब का विकास नहीं बल्कि शव का विकास' हुआ है। इसलिए, आज समय की यह मांग है कि आगामी लोकसभा चुनावों में सभी शुभ बुद्धि-संपन्न लोगों को एकजुट होकर, इस विभाजन की राजनीति, विद्वेष की राजनीति का बहिष्कार कर, महान भारत का निर्माण करना है।

पिछले पांच वर्षों में बी जे पी सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ असंतोष और आन्दोलन का पथ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने प्रदर्शित किया है। हम पर हमला करके, मामला करके, हमें डराने की कोशिश करने के बावजूद, हमने लोगों को साथ लेकर सबसे तीव्र विरोध किया इस स्वेच्छाचारी, एकनायकवादी शासक के खिलाफ। केंद्र द्वारा वंचना के बावजूद, पश्चिम बंगाल की माँ माटी मानुष की तृणमूल सरकार ने विकास का परचम लहराया है। पूरे देश के समक्ष, पश्चिम बंगाल प्रगति और विकास का पथ प्रदर्शक बन चुका है। जहाँ पूरे देश में 2 करोड़

रोजगारों में कमी आई है, और बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, वहां पश्चिम बंगाल में हमने एक दूसरा चित्र बनाया है। यहाँ बेरोजगारी में 40%की कमी हुई है। इसके अलावा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हमें ही देश में सर्वश्रेष्ठ ख़िताब मिले हैं। छात्र, युवा, नौजवानों को अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार के क्षेत्र में अवसर प्रदान किया जायेगा। SC/ST/OBC, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को भरना आवश्यक है। इसके अलावा नौकरी के क्षेत्र में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

बी जे पी की हिंसा और मारकाट की राजनीति के खिलाफ जाकर, हमने ही पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव का अनन्य उदाहरण स्थापित किया है। मैं व मेरा दल हमेशा, जनता के पास रहे, एवं भविष्य में भी रहेंगे। इसीलिए, देशवासियों से निवेदन है कि, आसन्न लोकसभा चुनावों में जहाँ जहाँ हमारे प्रार्थी हैं उन्हें विजयी बनाएं तथा कुशासन के घाव को भरकर, नए भारत के निर्माण में हमारे संग रहे। जहाँ जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां वहां बी जे पी-विरोधी प्रमुख शक्ति को विजयी बनाएं एवं अशुभ शक्ति बी जे पी को नकार दें। पूरे देश में शुभ बुद्धि-संपन्न लोगों के महा गठबंधन का निर्माण करें।

आसन्न लोकसभा चुनाव, भारत के इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस चुनाव में ही हम अपने भविष्य का चयन कर सकेंगे, हम अगली पीढ़ी को कौन सा भारत उपहार में देंगे, यह भी निश्चित कर पाएँगे। हमारे समक्ष दो रास्ते खुले हैं। या तो हम चुनेंगे धर्मनिरपेक्ष, युक्तिवादी, उदार, सहनशील भारत को, अन्यथा हमें चुनना पड़ेगा संकीर्ण, पिछड़नेवाले, सांप्रदायिक एक भारत को। यदि हम भारत के प्राचीन आदर्शों को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो, हम यदि इतिहास के आलोक में भारत के बहुलवाद उदारवादी आदर्श को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें एकजुट होकर रोकना होगा इस कट्टरपंथी व साम्प्रदायिक अशुभ शक्ति को। यदि हम अपने को वास्तविक रूप से देशप्रेमी समझते हैं, तो इस देश के सम्मान, आदर्शों की रक्षा करना हमारे ही हाथ में है। और यदि हम विभेदकारी, साम्प्रदायिक शक्ति के समक्ष झुक जाते हैं तो यह हमारे महापुरुषों द्वारा तिल-तिल कर स्थापित किये गए आदर्शों और मूल्यबोध की पराजय होगी। उदार, गणतांत्रिक, बहुलवाद, सहिष्णु, धर्मनिरपेक्ष भारत को पुनः महिमामंडित करना ही हमारा प्रमुख कर्तव्य है।

अशुभ शक्ति को पराजित कर, नए भारत का निर्माण करने के क्षेत्र में, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने सर्वदा अग्रणी भूमिका निभाई है। और भविष्य में भी देश के विकास का पथ प्रदर्शित कर सकता है हमारा गर्वोन्मुख पश्चिम बंगाल। हमारी सफलता ही सरकार चलाने के क्षेत्र में हमारी योग्यता को सिद्ध करती है। हमारे भाषणों में डंका पीटने की आवश्यकता नहीं है, हमारे विकास के कार्य ही हमारा परिचय हैं।

छात्र-युवा, नयी पीढ़ी के पथ प्रदर्शक हैं। उनको महत्व देते हुए, उन्हें विकास के कार्यक्रमों में शामिल करना व उनके रोजगार के लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। पश्चिम बंगाल, इस क्षेत्र में पूरे देश का पथ प्रदर्शक है।

महिला शक्ति को महत्व देते हुए, उन्हें देश व बंगाल के कल्याण हेतु आगे बढ़ाना होगा। दलितों का विकास करना, व उनके सम्मान को मर्यादा देते हुए, उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है।

आदिवासी भाई-बहनों को संपत्ति का अधिकार, पट्टे का अधिकार, शांति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, भाषा अधिकार व जंगल के अधिकार के साथ-साथ उनकी अपनी भाषा आलचिकी, कुडुक भाषा को भी उचित मर्यादा दी गई है तथा भविष्य में उनके हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

अल्पसंख्यक भाई-बहनों व अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) वर्ग के जीवन की सुरक्षा, धर्म निरपेक्षता व उनका विकास हमारा प्रमुख कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल में, हमने अपने कार्यों के जरिये, इस बात को प्रमाणित किया है।

पश्चिम बंगाल में सामान्य वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षा-संस्कृति-रोजगार सहित किसी भी कल्याणकारी कार्यों में पीछे नहीं हैं। उन्हें भी इस समाज में, स्वामी विवेकानंद मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति, कन्याश्री, युवश्री, सबुज साथी, रूपश्री, समव्यथी-सभी को सब में सामान मर्यादा मिल रही है।

सभी के लिए आहार, वस्त्र व रहने के लिए मकान तथा रोजगार मुहैया कराना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसी कारण पश्चिम बंगाल में 'दो रुपये किलो चावल' से लेकर सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए हमें

गर्व है। राज्य के लगभग 8.5 करोड़ लोग खाद्य साथी योजना से जुड़े हैं। इसके अलावा भी, हमने 7.5 लोगों को स्वास्थ्य साथी योजना से जोड़ा है। इस योजना के जरिये सरकारी अस्पतालों के अलावा, गैर सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सेवा दी जाती है। इस परियोजना में घर की महिलाओं को मिल रहा है स्मार्ट कार्ड।

महिला सशक्तीकरण के लिए 'कन्याश्री' योजना के विश्व जय करने में बाद, आज महिलाएं काफी आगे बढ़ गई हैं।

कृषि से लेकर उद्योग, उत्कर्ष बंगाल से लेकर संस्कृति-बंगाल आज सभी क्षेत्रों में आगे है और गर्वित भी। समतल से पहाड़ तक संपूर्ण विकास ही हमारा लक्ष्य है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, मिरिक, कार्सियांग पहाड़ व समतल क्षेत्र में विकास के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

केवल बंगाल ही नहीं अन्य राज्यों में भी यदि तृणमूल कांग्रेस अपनी शाखाएँ फ़ैलाए, तो वहां के लोगों को भी ये सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

मोदी सरकार की विदाई का घंटा बज चुका है। आप लोगों के समर्थन, आशीर्वाद, शुभ कामनाओं व दुआओं से नयी सरकार सत्ता में आने पर संगठित भारत, उन्नत भारत, लोकतांत्रिक भारत का गठन होगा, जहाँ एकनायक तंत्र का कोई स्थान नहीं होगा।

छात्र व युवक, कृषि व श्रमिक, खेतीहर मजदूर महिला, अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सहित हिन्दू-बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, मुसलमान-इसाई-सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी, विंध्याचल से द्वारका, नालंदा से वाराणसी, जयपुर से बंगाल, असम से उत्तर पूर्वांचल, झाड़खंड से ओडिशा, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, मध्य से उत्तर पूर्वी भारत, सागर से पहाड़, जंगलमहल से उत्तर बंगाल व दक्षिण बंगाल-सर्वत्र माँ माटी मानुष का कार्य देखकर, हमारे लिए आपके विश्वास, आशीर्वाद, दुआ व प्यार से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रत्येक प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट देकर

विजयी बनायें। असम, झारखंड, ओडिशा, अण्डमान, बिहार राज्य जहाँ तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे उन्हें विजयी बनाने का अनुरोध है। जहाँ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं हैं, वहाँ बीजेपी विरोधी शक्ति सह, क्षेत्रीय दल के प्रत्याशियों को अपना वोट देकर विजयी बनायें।

इसी के साथ, बी जे पी व अन्य राजनैतिक दलों द्वारा फैलाई जाने वाली बदनामी, षड्यंत्र, कुप्रचार, धन बल, पेशी बल आदि को परास्त कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। अभिन्न न्यूनतम कर्मसूची (Common minimum programme) के अनुसार संयुक्त भारत (United India) को हमें साकार करना है। बंगाल ही देश में विकास और समृद्धि का पथ प्रदर्शन करेगा।

एक्यबद्ध सर्वधर्म समन्वय व सर्वांगीण विकास के लिए

आपकी आशीर्वादधन्य

ममता
सभानेत्री
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

मोदी सरकार की पांच वर्षों की असफलता व कुशासन का दस्तावेज़

चापलूस समाचारपत्रों के गर्जन व उनके कौशलपूर्वक झूठ के बावजूद मोदी प्रशासन की विफलता को दबाकर रखा नहीं जा सकता.विफलता के कुछ उदाहरण -

1. मोदी सरकार के शासन में, भारत के कृषकों की चरम दुर्दशा -

   क) मोदी सरकार के शासनकाल में, निर्मम रूप से देश के कृषक उपेक्षित हुए हैं तथा कृषि अर्थनीति खतरे में पड़ गई है।यह सोच कर आश्चर्य होता है कि वर्ष 2014 से 2016 के बीच देश के 36,420 कृषक आत्महत्या करने पर मजबूर हुए थे।और उसके बाद से, सरकार कृषक आत्महत्या के आंकड़ों को प्रकाशित न कर, उसे दबा कर रख रही है।

   ख) यह शर्म की बात है कि मोदी सरकार के प्रथम चार वर्षों में कृषि जी डी पी की वृद्धि में बहुत कमी आई है।पहले चार वर्षों में जहाँ इस वृद्धि की दर थी 5.2 प्रतिशत,वहीं मोदी सरकार के प्रथम 4 वर्ष के कार्यकाल में यह घटकर 2.5 प्रतिशत हो गई।

   यहाँ तक की अक्टूबर-दिसंबर 2017 से अक्टूबर-दिसंबर 2018 के बीच कृषकों की आय 9.12 प्रतिशत से एकदम घटकर 2.04 प्रतिशत हो गई है।

   मोदी ने जहाँ वर्ष 2022-23 तक कृषकों की आय दुगुनी करने की बात कही थी,वहाँ पश्चिम बंगाल में आर्थिक वर्ष 2010-11 से 2017-18 के बीच कृषकों की आय 91,020 रुपए से तीन गुना बढ़कर 2,91,000 रुपए हो गई है।

   ग) वर्ष 2013 -14 में जहाँ कृषि निर्यात का सर्वोच्च परिमाण था 42.5 बिलियन अमरीकी डालर,वहीं मोदी सरकार के समय में वृद्धि की दर ऋणात्मक हो गई है।

   साथ ही, कृषकों को क्षतिग्रस्त कर कृषि आयात लगातार बढ़ रहा है।

   वर्ष 2013-14 में जहाँ आधिक्य निर्यात (Export Surplus) 25

बिलियन अमरीकी डालर था वहीं वर्ष 2017 -18 में यह घटकर 10 बिलियन अमरीकी डालर से भी कम हो गया है।

साथ ही वर्ष 2013-14 से देश में कृषि आधिक्य (Agricultural Surplus) में बढ़ोतरी हुई है,फसल की कीमतों में कमी आई है एवं लगभग सभी खाद्यानों के क्षेत्र में लाभ के अनुपात में भी कमी आई है।

कृषि क्षेत्र में इन हताशाजनक आंकड़ों से ही स्पष्ट है कि मोदी के शासनकाल में देश के कृषकों की चरम दुर्दशा हुई है।और इस भयानक दुर्व्यवस्था के कारण ही, पूरे देश के कृषक सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हुए हैं।मोदी के हाथ असहाय कृषकों के खून से रंगे हैं।

2) मोदी के शासनकाल में भ्रष्टाचार : खाया और खाने दिया

क) राफाल भ्रष्टाचार-

मोदी सरकार ने शासन में आने के बाद छाती ठोककर घोषणा की थी 'न खाऊंगा,न खाने दूंगा'। लेकिन वास्तविकता यह है कि 'खाया और खाने दिया'।केंद्र सरकार के सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार की जड़ें फ़ैल गई हैं। राफाल निंदनीय घटना में 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा सीधे अनिल अम्बानी को देने के लिए सुरक्षा मंत्रालय के सभी नियम कानून ताक पर रखने के लिए आज प्रधानमंत्री स्वयं दोषी के कठघरे में हैं।

आधुनिक भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार की यह सबसे बड़ी घटना है।

ख) एम एस एम ई 59 मिनट ऋण भ्रष्टाचार

इस भ्रष्टाचार पर कम आलोचना होने के बावजूद, भ्रष्टाचार के प्रकार के परिप्रेक्ष्य में एम एस एम ई 59 मिनट ऋण एक अन्यतम शर्मनाक एवं निंदनीय घटना है।ऑनलाइन पर इस ऋण की प्रक्रिया संचालन का दायित्व अहमदाबाद की फिनटेक कम्पनी कैपिटा वर्ल्ड को दिया

गया। उस कंपनी को काम देने के लिए टेंडर की नियमावली को नहीं माना गया।नियमों की अनदेखी कर उन्हें काम देने के कारण कैपिटा वर्ल्ड आवेदकों और बैंक से सिर्फ रुपए ही नहीं लेंगे बल्कि इसके साथ उनके हाथों में असंख्य लोगों के व्यक्तिगत दस्तावेज़ एवं तथ्य पहुँच जाएंगे जिनका दुरुपयोग हो सकता है।

कैपिटा वर्ल्ड को काम दिलाने के विषय की जांच होनी आवश्यक है और यह जानना भी जरुरी है कि इस भ्रष्टाचार में कितना रुपया लगा हुआ है।

वास्तव में बीजेपी शासित सभी राज्य दुर्नीतिग्रस्त है, वहाँ ना ही कानून है और ना ही शासन।

3. मोदी के शासनकाल में बैंकिंग क्षेत्र में भयावह क्षति : एन पी ए की चोरी में बढ़ोतरी

क) भारत का विशाल बैंकिंग क्षेत्र भी मोदी के शासनकाल में भयानक संकट में व उपेक्षा का शिकार बना। यह क्षेत्र भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है, जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा।

ख) यह भी एक भयानक घटना कि जहाँ वर्ष 2014 में देश में बैंकों का नॉन परफोर्मिंग एसेट-(एन पी ए) 2 लाख करोड़ (2,09,840 करोड़ रुपए) था जों वर्ष 2017-18 में बढ़कर 10 लाख करोड़ (10,36,187 करोड़ रुपए हो गया)। यानि मोदी सरकार के समय यह 5 गुना बढ़ गया।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मोदी सरकार के समय में बैंकों की स्थिति दुर्दशापूर्ण हुई।

ग) इससे भी शर्मनाक घटना ये है कि बड़े-बड़े उद्योगपति बैंक के साथ धोखाधड़ी करके विदेशों में चले गए हैं एवं भारत की पहुँच से बाहर हो गए हैं। एक ऐसी घटना भी सामने आई है कि एक उद्योगपति के

लिए लुकआउट नोटिस को 'गिरफ्तार' करने को बदल कर 'सूचना देने' के जरिये सी बी आई ने उसे भगाने में सहायता की। इसके कारण वह उद्योगपति बिना किसी बाधा के विदेश जाने में सफल हो गया।मोदी के शासनकाल में सी बी आई को किसने लुकआउट नोटिस को बदलने का निर्देश देकर उन्हें भागने में सहायता की?इस घटना की जांच होनी चाहिए और यथोचित दंड की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

घ) आर बी आई द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, मोदी शासनकाल में मई,2018 तक पिछले पांच वर्षों में लगभग एक लाख करोड़ रुपए की कुल 23,000 बैंक धोखाधड़ी की घटनाएँ घटी हैं।

4) मोदी शासनकाल में नोटबंदी : आम जनता को कष्ट में डालने का निर्मम निर्णय

क) 8 नवम्बर 2016 को नरेन्द्र मोदी ने विध्वंसात्मक नोटबंदी के निर्णय की घोषणा की।इस निर्णय के कारण देश के लाखों कृषकों का जीवन अपार कष्टमय हो गया,असंख्य असंगठित क्षेत्र के व्यवसायी जर्जरित हो गए थे।इस निर्णय के कारण लघु और मध्यम उद्योगों को व्यापक क्षति झेलनी पड़ी थी।निरस्त नोटों का 99.3 प्रतिशत ही जब बैंक में लौट आया तब जनता के मन में संदेह जगा कि नोटबंदी का असली कारण लाखों करोड़ों रुपए के काले धन को सफ़ेद करने की सुविधा देने का एक बड़ा घोटाला हो सकता है। भारत सरकार ने स्वयं कहा कि 3 लाख से ज्यादा बैंक खातों का हिसाब नहीं मिला।लगभग 80,000 केस मोदी सरकार ने अपने हाथ में लिए लेकिन काले धन के लिए कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ।

ख) नोटबंदी के कारण लाखों रुपए की क्षति हुई,जीडीपी वृद्धि घटी व राजकोष में भी कमी परिलक्षित की गई,जीएसटी संग्रह में मंदी,रोजगार वृद्धि को धक्का,कृषक आत्महत्या,निर्यात ह्रास,लघु व्यवसायों को चरम

संकट व असंगठित क्षेत्रों की भयानक दुर्दशा।और इन सबके कारणों से लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ गया।

5) नोटबंदी के साथ जुड़ गया बिना किसी तैयारी के जी एस टी का क्रियान्वयन और उसके लिए मोदी सरकार का झूठी बहादुरी का दिखावा : आम जनता को दुगुनी हैरानी

क) नोटबंदी के भयानक निर्णय के बाद एक बार फिर नई परेशानी लेकर आया यथोचित तैयारी के बिना ही जी एस टी का क्रियान्वयन।असल में संसद भवन के सेंट्रल हॉल से जी एस टी का डंका पीटना राजनैतिक सुविधा पाने के अलावा और कुछ नहीं था।

यथोचित ढांचा तैयार किए बिना जी एस टी को लागू करने से भारत के लघु व मझोले उद्योगों को ध्वस्त होने की दिशा में ढकेल दिया गया।

उल्टे, अपर्याप्त जी एस टी नेटवर्क (जी एस टी एन) प्रचुर काला धन बना रहा है तथा हवाला सौदों को जन्म दे रहा है। जाली इनवॉइस के इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा रहा है, जो काला धन बना रहा है।

ख) पश्चिम बंगाल ने इन मुद्दों के लिए केंद्र सरकार को पहले ही सतर्क किया था एवं केंद्र को जुलाई 2017 में ही सलाह दी थी कि जी एस टी शुरू न करे।अब केंद्र सरकार की नींद टूटी है और लोगों को दिखाने के लिए यहाँ-वहां कुछ-कुछ तलाशी ली जा रही है। मुख्य बात ये है कि वास्तविकता बोधहीन मोदी शासनकाल में देश के गरीब व छोटे व्यापारी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं।

6) मोदी कुशासनकाल में बेरोजगारी कई गुना बड़ी है जिसने गरीबों को बहुत क्षति पहुंचाई

क) मोदी शासनकाल में बेरोजगारी कई गुना बढ़ी है जिसके कारण बहुत से परिवारों पर मुसीबत टूट पड़ी है।नोटबंदी और बिना तैयारी के जी

एस टी लागू करने के बाद ही बेरोजगारी में वृद्धि की दर देखने लायक हो गई है।

वर्ष 2017में जहाँ बेरोजगारी की दर 4.50प्रतिशत थी वहां वर्ष 2018 में यह बढ़कर 5.96 प्रतिशत हो गई।

यह एक भयानक बात है कि स्वनामधन्य सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में 1.1 करोड़(11मिलियन) लोगों ने देश में अपनी नौकरी खोई है। इससे ज्यादा और भी कष्टदायक है कि नौकरी खोने वाले ज्यादातर ग्रामीण असंगठित क्षेत्रों से हैं।

यह संदेहातीत है कि इस बेरोजगारी की वृद्धि के फलस्वरूप देश के आम युवक-युवतियां सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं एवं इस घटना ने भारत की ख़राब आर्थिक स्थिति को ही प्रदर्शित किया है।

ख) दूसरी ओर, केंद्र सरकार के लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार ही पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बेरोजगारी घटी है।केंद्र सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2012 -13 से वित्तीय वर्ष 2015-16 इन चार वर्षों में,40 प्रतिशत बेरोजगारी घटी है।पश्चिम बंगाल की इस सफलता के पीछे यह कारण है कि लेबर इंटेंसिव क्षेत्र में राज्य की सतर्क दृष्टि और कौशल क्रियाकलाप तथा साथ ही हमने औसत जी डी पी वृद्धि पर भी नज़र रखी है।

केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियां रोजगार नहीं बल्कि बेरोजगारी को जन्म देती हैं, जबकि पश्चिम बंगाल ने रोजगार के जरिये समृद्धि की दिशा दिखाई है।यह भी मोदी सरकार की एक और विफलता है।

7) बातों की फुलवारी के बावजूद मोदी सरकार माँ-गंगा के क्षेत्र में भी असफल

क) मोदी के आवेग प्रवण भाषण में प्रमुख है गंगा को माँ कहना। लेकिन वास्तविकता यह है कि नमामि गंगे परियोजना में गंगा की सफाई के क्षेत्र में भी मोदी सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। मोदी की नजर के

सामने रहने के बावजूद देश ने देखा कि बातों के कौशल के बावजूद नमामि गंगे परियोजना के जरिए गंगा की सफाई में भी मोदी विफल रहे हैं।

ख) पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में मोदी की विफलता स्पष्ट हो जाती है जब पर्यावरण परफोर्मेंस इंडेक्स के अनुसार 180 देशों में भारत का स्थान 177वॉ है। कितनी लज्जाजनक बात है!!

8) 'मेक इन इंडिया' में मोदी सरकार की सम्पूर्ण विफलता - निवेश वृद्धि की दर घटती हुई

क) देश में निवेश वृद्धि व मूलधन बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' का नारा तैयार किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह प्रमाणित है कि यह एक झूठ के अलावा कुछ नहीं है एवं असल में मोदी सरकार ने अपनी विफलता की छवि ही बनाई है।

ख) देश के ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फार्मेशन (जी ऍफ़ सी ऍफ़) के द्वारा देश में निवेश वृद्धि को नापा जाता है।इस वृद्धि की दर को बहुत बड़ा धक्का लगा है नोटबंदी,जीएसटी व मोदी सरकार की अन्य भ्रान्तिमूलक नीतियों के कारण।वर्ष 2016-17 में निवेश की दर 10.14प्रतिशत थी व वर्ष 2017-18 में यह एक धक्के से घटकर 7.36 प्रतिशत पर आ गई। यह आंकड़ा ही प्रमाणित करता है कि मोदी का 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम पूरी तरह से विफल रहा।

ग) तथ्यों के आधार पर मोदी शासनकाल में भारत में सीधे विदेशी निवेश की स्थिति भी हताशापूर्ण है

एक तरफ मोदी ने 55 महीनों में 92 देशों के विदेश सफर का रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए जो आम जनता के टैक्स से ही लिया गया। ढोल बजाकर कहा गया था कि इन विदेश सफर से भारत को बड़े निवेश प्रस्ताव मिलेंगे।

लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के आंकड़े देखने पर समझा जा सकता है कि निवेश लाने की यह बात भी असल में एक झूठ ही है।

वर्ष 2015-16 में भारत में एँफ़ डी आई की वृद्धि की दर 27.28 प्रतिशत थी और मोदी ज़माने में यह वृद्धि की दर वर्ष 2016-17 में 5.99 प्रतिशत घटी है.एवं वर्ष 2017 -18 में यह और घटकर 6.60 प्रतिशत हो गई।

आर बी आई द्वारा इस तथ्य से पोल खुल गई है। विदेशी निवेश लाने में भी मोदी सरकार विफल रही। और इसके बाद तो 'मेक इन इंडिया' का नारा प्रहसन के अलावा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है।

9) नागरिकता बिल पर भी मोदी सरकार की विफलता

क) नागरिकता से सम्बंधित विषय पर मोदी सरकार द्वारा गृहित नीतियाँ जैसे सिटीजनशिप (संशोधन बिल),असम में नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ़ सिटीजन (एन आर सी), अरुणाचल प्रदेश में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट (पी आर सी)ने उत्तर पूर्वी राज्यों को अशांत कर दिया है एवं भविष्य में दूसरे राज्यों में भी अशांति हो सकती है।

ख) नागरिकता के मुद्दे पर मोदी सरकार निर्णयहीनता से ग्रस्त है एवं इस कारण उत्तर-पूर्व के राज्यों में अशांति की आग लग गई है और वहां के कई लोगों को अनिश्चित भविष्य की ओर ढकेल दिया गया है।

ग) मोदी सरकार की अयोग्यता व विफलता का यह एक और उदहारण है।

10) खुले अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी का झूठा भाषण

विभिन्न जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विभिन्न प्रकल्पों या काम की सफलता के बारे आधारहीन दावे किये हैं। उनके भाषणों में निम्नलिखित क्षेत्रों की झूठी सफलता का बार बार उल्लेख किया गया है-

क) ग्रामीण स्वास्थ्य परिसेवा व स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण

ख) उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एल पी जी कनेक्शन

ग) ग्रामीण विद्युतीकरण

घ) ब्रॉडबैंड कनेक्शन

ड़) बैंक अकाउंट खोलने की संख्या

दिल्ली में आज चाहिए जनता की सरकार

भारत की जनता के प्रति
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का निवेदन

इस घोषणापत्र को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से भारत की जनता के समक्ष प्रथम व द्वितीय भाग में उल्लिखित कुछ उद्वेगजनक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस घड़ी देश को विभाजन, घृणा के हाथों से बचाना हमारा कर्तव्य है। भारतवर्ष की एकता के सतरंगी इन्द्रधनुष का सृजन करना और इस एकता को पुनः स्थापित करना हमारा दायित्व है।

1. हमारा विश्वास है कि लोकतांत्रिक राजनीति में सभी लोगों, धार्मिक विचारों व विश्वासों का समान स्थान है।

2. इसलिए हमारा विश्वास धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष में है।

3. हमारे संविधान में उल्लिखित संघीय ढाँचे पर हमारा विश्वास है। देश के विकास के लिए राज्यों की क्षमतावृद्धि अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, हमारा विश्वास है कि संविधान में उल्लिखित नियमों के अनुसार हमारे देश की केंद्र सरकार सकारात्मक और एक्यमूलक होनी चाहिए।

4. जब हम एकता की बात करते हैं तो हम इस बात से अवगत हैं कि हमारे देश के एक बड़े हिस्से में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में, वे हमारे समाज, आर्थिक नीति व राजनीति में उपेक्षित और अवहेलित हैं।

5. हम इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नीति में इन पिछड़े लोगों को सम्मान सहित मूलधारा में लौटाना अत्यंत आवश्यक है, जो मोदी सरकार के शासनकाल में पिछले 5 वर्षों में समाप्त हो गया था.

   हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में, अल्पसंख्यक समुदायों का बहुत विकास हुआ है ।

   बंगाल, देश में आज अल्पसंख्यक छात्र -छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के क्षेत्र में अव्वल है । 2 करोड़ 3 लाख से अधिक अल्पसंख्यक स्कालरशिप दी गई हैं, जिसका आर्थिक मूल्य 5257 करोड़ रुपये से अधिक है।

   अल्पसंख्यक वर्ग के व्यवसायियों को ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में बंगाल

पूरे देश में प्रथम है। 8 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक युवक-युवतियों को स्वरोजगार के लिए1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया गया है ।

अपने राज्य के इस विकास का उदाहरण, हम राष्ट्रीय क्षेत्र में व सभी राज्यों में लागू करना चाहते हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अन्य पिछड़ों वर्ग (OBC) में सूचीबद्ध कर, उन्हें आरक्षण के क्षेत्र में लाया गया है। इसके फलस्वरूप, राज्य की 94 प्रतिशत मुस्लिम आबादी आज संरक्षण के दायरे में है। यह उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं की संख्या को कम किए बगैर ही, अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्र-छात्राओं की सीटों की संख्या में 17 प्रतिशत संरक्षित किया गया है। इसके कारण कुल सीटों की संख्या में यथासंभव वृद्धि की गई है।

अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ हमने विभिन्न भाषा के लोगों के भाषाई विकास हेतु कई कदम उठाए हैं-

हम पश्चिम बंगाल राज्य की सफलता से आगे बढ़ने की शिक्षा ग्रहण करेंगे।

हिंदी भाषा को राज्य में सरकारी भाषा का सम्मान दिया गया है। प्रसंगतः उल्लेखनीय है कि हिंदी के अलावा उर्दू, नेपाली, पंजाबी, संथाली, ओडिया, कामतापुरी, राजवंशी, कुडुख व कुड्माली भाषाओं को बंगाल में सरकारी भाषा का सम्मान दिया गया है।

हमने बड़े पैमाने पर सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र के पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया जारी रखी है।

वर्ष 2014-15 से शिक्षाश्री परियोजना के ज़रिए, 70 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है।

1 करोड़ साइकिलों को सबुज साथी परियोजना के अंतर्गत वितरित किया गया है।

अपने अनुभवों से सीखकर, हमारा लक्ष्य पूरे देश के अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाना है।

हमारे राज्य में हमने पिछले सात वर्षों में प्रायः 65 लाख अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को जाति प्रमाणपत्र दिए.फलस्वरूप कोई जाति प्रमाणपत्र लंबित नहीं है।

6. राष्ट्रीय क्षेत्र में महिला व कन्याओं के विकास से सम्बंधित नीति में प्राथमिकता दी जाएगी।

हमें इस बात पर गर्व है कि 18 साल तक की लड़कियों के विकास के लिए बनी कन्याश्री योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च स्वीकृति मिली है । 62 देशों की 552 सामाजिक परियोजनाओं में से कन्याश्री को ही सर्वोत्तम चुना गया।

कन्याश्री परियोजना में वार्षिक आय की अधिकतम सीमा को खत्म कर दिया गया है-फलस्वरूप अब सभी कन्याएँ 'कन्याश्री' है। राज्य में 50 लाख से अधिक 'कन्याश्री' है। इस परियोजनांतर्गत 18 वर्ष की आयु के बाद अविवाहित रहकर पढ़ाई जारी रखने वाली कन्या को एकमुश्त 25 हजार रुपये दिये जाते हैं।

1 अक्टूबर 2013 से, कन्याश्री परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने 6,580 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। कन्याश्री का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' परियोजना 2 वर्ष बाद 22 जनवरी 2015 को आई, लेकिन इसमें 562 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

हमारा लक्ष्य, पूरे भारत में, अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति-प्राप्त कन्याश्री योजना को लागू करना है।

7. भारत की आर्थिक स्थिति को सम्यक् रूप से समझने के लिए हम विशिष्ट अर्थनीति विशेषज्ञ व अन्य विशेषज्ञों की सलाह लेकर आर्थिक कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। हमारी आर्थिक नीति 7 से 10 प्रतिशत जी डी पी तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका लक्ष्य विशेष रूप से रोजगार सृजन करना भी है।

पश्चिम बंगाल में हमने प्रमाण दिया है कि हमारी जी डी पी पूरे देश की तुलना में कुछ ज्यादा है। इतना ही नहीं, राज्य में बेरोजगारी के क्षेत्र में भी 40 प्रतिशत की कमी आई है(भारत सरकार के अधीन श्रम विभाग के अनुसार)। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2018-19 के बीच पश्चिम बंगाल में लगभग 1 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए (99.22 लाख)।

इस सफलता का कुछ श्रेय प्रतिफलन श्रम सघन क्षेत्र एवं रोजगार सृजन पर हमारी विशेष नजर को जाता है। वर्ष 2010-11 के 89 लघु व मध्यम उद्योग अब बढ़कर 522 हो गए हैं। फलस्वरूप, नौकरियां भी बढ़ रही हैं ।

हम सभी राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी स्वयं की दक्षता के चयन में सहायता करेंगे श्रम सघन उद्योग स्थापित करने में। इन श्रम सघन उद्योगों में उत्पादित अधिकांश वस्तुएं निर्यात करने योग्य हैं।

भविष्य में, अल्पकालीन व दीर्घकालीन रोजगार सृजन, उद्योग सृजन व कृषि सृजन में विभिन्न माध्यमों से वैश्विक स्तर पर देश को आगे ले जायेंगे। रोजगार वृद्धि एवं भारत के विकास को विशेष महत्व दिया जायेगा। हम लोग प्रतिष्ठित एवं संभावनामूलक क्षेत्र में विशेष नजर रखेंगे। हम लोग भविष्य में इस क्षेत्र में तकनीकी जैसे ब्लाक चेन एवं ए आई संबंधी अनुसंधान में खुद को शामिल रखेंगे।

हम संपूर्ण दृष्टि से आम लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्र में जीवन के मान वृद्धि का ख्याल रखेंगे। तकनीकी शिक्षा का उपयोग हम मनुष्य के कल्याण के लिए करेंगे। 'फ्रंकेंसटाइन' का सृजन नहीं करेंगे।

रोजगार व विकास की नीति हमारी दक्षता बढ़ाने तथा युवक-युवतियों को रोजगार दिलाने में सहायता करेगी जिसके फलस्वरूप पूरे देश में डेमोग्राफिक लाभ्यांश का परिमाण बढ़ेगा एवं डेमोग्राफिक हानि नहीं रहेगी।

विकास के इस मॉडल के जरिए यह स्पष्ट कि हम आत्मनिर्भर हैं और इसी पर आधारित परिकल्पना के माध्यम से हम देश की युवा शक्ति को रोजगार की राह दिखा पाएँगे।

8) हम नेशनल स्ट्रेटाजिक पेट्रोलियम रिज़र्व बनाएँगे। इस रिज़र्व में, 45 दिनों का लक्ष्य रखके, हम अतिरिक्त स्टॉक रखने की व्यवस्था करेंगे जिससे पेट्रोलियम का मूल्य आम जनता के लिए स्थितिशील अवस्था में रहेगा। वर्तमान में, इस रिजर्व की मात्रा 5-6 दिन के लिए है। मोदी सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रहीं। यद्यपि पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हो गई हैं। हाइड्रो कार्बन के क्षेत्र में यह, मोदी सरकार की आम जनता के प्रति निष्ठुरता का परिचायक है एवं दूरदर्शिता के अभाव का एक उदाहरण है।

9) आम जनता व सरकार के बीच पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हम विश्व की श्रेष्ठ इ-गवर्नेंस व्यवस्था स्थापन करेंगे। हम इस क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल से शिक्षा ले सकते हैं।

10) हम अनुश्रवण के लिए एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं कारगर संगठन का गठन करेंगे जिससे केंद्र सरकार की समस्त परियोजनाएं सफल हों। हम दूसरे राज्यों को भी इस तरह, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे।

11) केंद्र सरकार की सभी परियोजनाओं की क्रियान्वयन की समय-सीमा को कम करेंगे, जिससे आम जनता को द्रुत और उन्नत परिसेवा दी जा सके।

12) हम लोकपाल और लोकायुक्त को सभी राज्यों में लागू करेंगे, जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो और राज्य संचालन में पारदर्शिता रहे।

13) पंचायती राज को हम और सफलतापूर्वक लागू करेंगे ताकि गवर्नेंस का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा तृणमूल स्तर की इस संस्था की हम लोकतंत्र के जरिए रक्षा कर सकें।

14) हम सर्वदा सुधार के ज़रिए, चुनावों में पारदर्शिता लाने के पक्ष में हैं। We want electoral reform। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से सीख लेते हुए, हम सभी स्तरों पर चुनाव सम्बंधित सुधार करेंगे... इससे लोकतांत्रिक राजनीति से भ्रष्टाचार दूर रहेगा। हम 62 देशों में लागू हुई संस्था की तरह, यहाँ भी सरकार के कोष से एक निर्वाचन संस्था व्यवस्था का निर्माण करेंगे। इन देशों में शामिल हैं - थाईलैंड, मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे

विकासशील देशों के साथ-साथ यू के, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे उन्नत देश भी।

15) छात्र व युवक, कृषि व श्रमिक, खेतीहर मजदूर, महिला, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सहित हिन्दू-बौद्ध-सिख-जैन-पारसी-मुसलमान-ईसाई- सभी धर्मों के लोगों को शामिल कर, कश्मीर से कन्याकुमारी, विंध्याचल से द्वारका, नालंदा से वाराणसी, जयपुर से बंगाल, असम से उत्तर-पूर्वांचल, झाड़खंड से ओडिशा, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, मध्य से उत्तर-पूर्व भारत, सागर से पहाड़, जंगलमहल से उत्तर बंगाल व दक्षिण बंगाल - सर्वत्र माँ-माटी-मानुष का विकास व समृद्धि कर, हम एक नये भारत का निर्माण करेंगे।

16) हम विचार व्यवस्था (judiciary) को पूरी स्वतंत्रता देंगे।

17) हम जमे हुए केसों के पहाड़ के निष्पादन हेतु विचार व्यवस्था में संशोधन करेंगे। इस संशोधन के अंतर्गत, देश की सभी निचली और उच्च अदालतें शामिल होंगी। हम देश में पर्याप्त अर्थ बल से फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे ताकि कानून व्यवस्था में गति आ सके।

हम महिलाओं के लिए विशेष कोर्ट बनाएँगे। महिलाऐं देश की आधी आबादी हैं। महिला अनुसूचित जाति/जनजाति, नाबलक, नाबलिकाओं इत्यादि पर हुए अत्याचारों को द्रुत न्याय मिलेगा। इस दर्शन को लागू करने के लिए, देश की निचली से लेकर उच्च अदालतों में पर्याप्त संख्यक न्यायधीशों की आवश्यकता है। हम इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को लेने से पीछे नहीं हटेंगे।

18) सभी के लिए स्वास्थ्य - इस लक्ष्य के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय को हम जी डी पी के एक महत्वपूर्ण अंश के रूप में विवेचना कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य इसे वर्तमान के 1 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत करना है।

- हमारा लक्ष्य देश के प्रत्येक गाँव में स्वास्थ्य सेवा पहुँचाना है।
- सभी के लिए स्वास्थ्य परियोजना में हम माँ व शिशु को प्राथमिकता देंगे।

- हम पूरे देश में शिशुओं के लिए विशेष Sick Neonatal Care Unit (SNCU) व Sick New Born Stabilization Unit स्थापित करेंगे।
- पश्चिम बंगाल की तरह ही, सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह निशुल्क दवाएं, चिकित्सा व रोग निदान की व्यवस्था करेंगे।
- हमारा संकल्प, 5 लाख रुपये वार्षिक आय वाले समृद्ध सभी भारतीय नागरिकों को एक स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लाना है।
- इसके अलावा 6 लाख रुपए वार्षिक आय वाले वृद्ध व्यक्तियों को मिलेगी निःशुल्क मेडिकल परिसेवा।
- हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश में प्रिवेंटिव केयर बढ़े एवं आम लोगों का स्वास्थ्य खर्च घटे।
- हम प्राचीन चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गवेषणा व विकास करेंगे।
- मह्कमा स्तर पर हम मल्टी व सुपरस्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करेंगे। पश्चिम बंगाल में हमने ऐसे 43 अस्पताल स्थापित किए हैं।
- हम कॉलेजों में डॉक्टर, नर्स, पेरामेडिक, डायग्नोस्टिक तकनीशियनों की सीटें बढ़ाएँगे।
- हम ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग देकर लोगों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

19) हमारा लक्ष्य ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को 100% करना है। हम सभी राज्यों, जिलों व राष्ट्रीय सड़क को जोड़ने वाली परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वचनबद्ध हैं।

20) स्वाधीनता के 71 वर्षों के बाद, अभी भी देश के अनेक गाँवों में पेयजल नहीं है। निर्दिष्ट समयसीमा में हम देश के प्रत्येक गाँव में पहुँचाना चाहते हैं शुद्ध पेयजल। जिन विशेष जगहों पर आर्सेनिक, फ़्लोराइड या नमक की समस्या है, वहां द्रुतता से समस्या का समाधान करना चाहते हैं ।

21) शिक्षा के क्षेत्र में हम खर्च को जी डी पी के 6 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते हैं। वर्तमान में इसका परिमाण 3 प्रतिशत (3.24) है। हमारी आशा है कि इसका 70 प्रतिशत स्कूलों में व बाकी 30 प्रतिशत उच्च शिक्षा व मानव संसाधन गवेषणा में लगाया जाएगा।

- हम शिक्षा के मान का विकास करेंगे और साथ ही छात्र-छात्राओं की संख्या को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे।
- हम एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे जो रोजगार मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाएगी। लेकिन किसी भी तरह ज्ञान अर्जित करने का मार्ग बंद नहीं होगा। विशेष शिक्षा व्यवस्था लिबरल आर्ट के नाम से जानी जाएगी। विशेषज्ञों की यह समिति केंद्र सरकार का मार्गदर्शन करेगी एवं राज्य सरकारों को शिक्षा से संबंधित नीति निर्धारण करने व उसे ऊँचाई तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- पिछले साढ़े सात साल में राज्य में 28 नए विश्वविद्यालय व 50 नए कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 11 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।
- पिछले साढ़े सात साल में राज्य में 8 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। 10 और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं।
- विश्व के उदाहरण को सामने रखकर हमारे देश के छात्र-छात्राओं को दीर्घकालीन शिक्षा ऋण दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के इस उदाहरण को सामने रखते हुए, पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के स्तर के विकास की ओर ध्यान देंगे।

22) आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए नई योजना लाएंगे, जिससे उन्हें गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी दक्षता व रोजगार की विशेष सुविधा मिलेगी। देश की युवा शक्ति को हम व्यवसाय के हर क्षेत्र में सहायता करेंगे।

23) कृषि के साथ मछलीपालन, पशुपालन को प्राथमिकता दी जाएगी।

- हम देश के कृषकों द्वारा उत्पादित चावल, पटसन, गेहूं व अन्य प्रमुख अनाजों के उत्पादन का यथोचित संग्रह मूल्य प्रदान करेंगे।

- हम कृषकों के उत्पादन की बड़े पैमाने पर वृद्धि के लिए विशेष कृषक उत्पादन परियोजना शुरू करेंगे।

  हमारी विशेष नजर उच्च मान के बीज उत्पादन आपूर्ति एवं गवेषणा पर है। इस क्षेत्र में, कृषकों को एक स्थिर आर्थिक स्थिति देने के लिए हम शस्य विभाजन व बहु - फसली व्यवस्था की परिकल्पना है।

- पूरे देश में किसानों को ऋण केवल किसान क्रेडिट कार्ड तक सीमित न रखकर, हम कृषकों के लिए ऋण सम्बंधित एक मुकम्मल नीति पर विचार कर रहे हैं।

- छोटे व सीमांत कृषक, जो ऋण लेकर उसे चुका नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ऋण माफ़ी की एक विशेष स्कीम हमारी योजना में है।

- कृषि व कृषि से सम्बंधित क्षेत्रों में सटीक तकनीक के लिए एवं गांवों में रोजगार के लिए हमारे पास विशेष योजनाएं हैं। गांवों का विकास इस मॉडल का प्रमुख अंग होगा। कृषकों के बच्चों को तकनीकी विकास व शिक्षा की सुविधा दी जाएगी।

- देश के तटीय मछुआरों व स्थलीय मछुआरों के लिए हम एक स्थिर विकास की योजना शुरू करेंगे। छोटे व सीमांत मछुआरों के विकास को हम प्राथमिकता देंगे।

- राष्ट्रीय पशु संसाधन नीति पर हम पुनर्विचार करेंगे। हमारा विशेष ध्यान कृषकों व छोटे पशुपालकों पर होगा।

- मुर्गीपालन कृषि का एक प्रमुख सहयोगी क्षेत्र है एवं इस क्षेत्र से कई महिलाऐं जुड़ी हैं। हम इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष उत्साह प्रदान करेंगे।

- दुग्ध क्रांति की गति को बनाए रखने के लिए पूरे देश में हम वैल्यू एडेड दुग्धजात वस्तुओं (घी, मिठाई, कन्फेक्शनरी आदि) पर विशेष ध्यान रखेंगे।

24) देश में फूड प्रोसेसिंग उद्योग अभी भी बहुत पिछड़ा है। ऐसा माना जाता है कि देश में उत्पादित फलों का 40 प्रतिशत नष्ट हो जाता है। इसका मुख्य कारण देश में पर्याप्त संख्यक कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हम इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देंगे। इसमें शामिल करेंगे सौर शक्ति चालित भंडारगृह। इसके अलावा कोल्ड चेन के जरिए कोल्ड कंटेनर परिवहन के लिए भी पर्याप्त योजनाएं रहेंगी।

हमारे पास कच्चे माल को प्रसंस्कृत करने की विशेष परिकल्पनाएं हैं। इस क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंडों को मान कर ही आगे बढ़ेंगे।

खाद्य प्रसंकरण पर विशेष ध्यान देने के फलस्वरूप 'खेतों से लेकर टेबल' तक विभिन्न स्तरों पर कई रोजगार सृजित होंगे।

25) देश में लघु, मध्यम व कुटीर उद्योग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अधूरे जी एस टी के कारण यह क्षेत्र विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है।

- हम देश के अति लघु, लघु, मध्यम संस्थाओं के लिए उन्नत तकनीकी शिक्षा लाना चाहते हैं। यह क्षेत्र भविष्य में रोजगार व वाणिज्यिक संगठन के क्षेत्र में सबसे निचले स्तर पर विशेष भूमिका का पालन करेगा।

- पश्चिम बंगाल में एम एस एम ई की सफलता निर्विवादित है। हमारे शासनकाल में एम एस एम ई यूनिटों की संख्या 49 से बढ़कर 520 हो गई है। बंगाल इस क्षेत्र में ऋण देने के लिए देश में प्रथम है। वर्ष 2017-18 में ऋण का परिमाण 44,000 करोड़ रुपए था। पश्चिम बंगाल में अब एम एस एम ई को ऋण देने के लिए सहकारी बैंकों को भी जोड़ा गया है।

26) देश के असंगठित क्षेत्र में बहुत से लोग काम करते हैं। इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाईजेशन के हिसाब से, भारत में 527 लाख कार्यरत लोगों में से 92 प्रतिशत लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। और इस विशेष क्षेत्र में लघु और अति लघु व्यावसायिक संगठन जुड़े हैं । बैंक फाइनेंस, तकनीकी विकास मार्केटिंग एवं दक्षता वृद्धि के जरिए हम इस विशेष क्षेत्र पर ध्यान देंगे। इस

विशेष क्षेत्र में कोई क्लस्टर बनाया जा सकता है कि नहीं इस पर भी हम ध्यान देंगे। हम इसके लिए एक विशेष टास्क फ़ोर्स बनाएँगे जो हमें नीति चयन में सहायता करेगी।

27) स्वाधीनता के 71 वर्ष के बाद भी जी डी पी का केवल 26 प्रतिशत तकनीकी क्षेत्र से आता है और 16 प्रतिशत आता है उत्पादन उद्योग से।

हमारी एक राष्ट्रीय उद्योग नीति होनी चाहिए जो उत्पादन उद्योग, खनन उद्योग, विद्युत् व अन्य उद्योगों को एक छत्र के नीचे लाएगी। यह पालिसी औद्योगिक गवेषणा को इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट शिक्षा के साथ जोड़कर देश को विश्व के तकनीकी क्षेत्र में आगे रखेगी। औद्योगिक निर्यात इस नीति का अविभाज्य अंग होगा।

28) सूचना प्रोद्योगिकी व उससे जुड़े उद्योग बहुत तेजी से बदल रहे हैं। बैक ऑफिस, बी पी ओ के दिन समाप्त हो रहे हैं। इसलिए हम भारत को विश्व के समक्ष आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एवं डाटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में एक उज्ज्वल नक्षत्र के रूप में प्रमाणित करना चाहते हैं।

इन सभी क्षेत्रों को हम औद्योगिक आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विकास व अन्य सामाजिक अवसंरचना से जोड़ना चाहते हैं। इसी कारण एक सम्पूर्ण आई टी पालिसी की आवश्यकता निर्विवादित है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात हमारे देश पर एक बोझ की तरह है, हम उसका भी समाधान चाहते हैं।

29) हम उद्योग बंधु कानून शुरू करना चाहते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ श्रमिक व मैनेजमेंट आपसी सहयोग से श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे। एक उच्च क्षमताशाली परिषद् इस पूरे मामले का अनुश्रवण करेगी।

30) देश के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वहां की स्थानीय व सनातन संस्कृति को उत्साहित करने के लिए हम प्रत्येक राज्य के साथ सहयोग कर एक नेशनल कल्चरल डेवलपमेंट काउन्सिल का गठन करना चाहते हैं।

पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक ग्रामीण व लोक कलाकारों को भत्ता व मेडिकल बीमा दिया जाता है।

आंचलिक सिनेमा, थिएटर, संगीत व जात्रा के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

31) देश के पिछड़े जिलों की आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

32) हमारे देश के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को सहयोग देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। देश के पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग, मिरिक, दार्जिलिंग, कार्शियॉग ये सभी पहाड़ी क्षेत्र हमारे गर्व हैं। इन क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए सरकार सदैव तत्पर है। इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए हम देश के समस्त पहाड़ी अंचल के लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे। इसी प्रकार 'सप्त सिन्धु'क्षेत्र भी हमारे लिए विकास का प्रमुख केंद्र रहेगा।

33) यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि विशेष आर्थिक सहायता के बावजूद देश के उत्तर -पूर्वी राज्यों में विकास संतोषजनक नहीं है। हम दृढ़ता से उत्तर, पूर्वांचली राज्यों के लिए वास्तविक, मजबूत, मनुष्य केन्द्रिक व पर्यावरण के लिए आवश्यक विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय ले रहे हैं। हम 66 वन, वृहद् हाईडल पावर पोटेंशिअयल, प्रमुख एग्रो प्रोसेसिंग सुविधाएँ, परंपरागत टेक्सटाइल, असाधारण पर्यटन व्यवस्था के द्वारा झाड़खंड, ओडिशा, अंडमान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं सिक्किम के संपूर्ण विकास की योजना है। वृहत्तर भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर इन राज्यों का विकास, भविष्य में इन राज्यों को एशिया के अन्य देशों के साथ वाणिज्यिक संपर्क बढ़ाने में सहायता करेगा।

34) अपने देश के ट्राइबल क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जाएगा।

35) हमारा संकल्प, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना व एक राष्ट्रीय परियोजना को शुरू करना है। यह पर्यटन व्यवस्था को उन्नत करेगी जहाँ विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले लोग काम करते हैं और जहाँ सर्वाधिक रोजगार के अवसर हैं। हमारा लक्ष्य केवल वर्तमान के पर्यटन स्थानों पर जोर देना ही नहीं है बल्कि

हमारे देश के अन्दर ही विभिन्न नए-नए पर्यटन स्थानों को ढूँढना भी है। हम ग्रामीण पर्यटन के विकास के साथ-साथ पर्यटन के लिए अवसंरचनागत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान देंगे।

36) हम जानते हैं कि वाणिज्य, व्यवसाय व शहरीकरण के कारण पर्यावरण की क्षति होती है। पर्यावरण परिवर्तन के लिए हमारे देश ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हम हरित व निर्मल पर्यावरण को बनाए रखने के लिए गम्भीरतापूर्वक वचनबद्ध हैं इसलिए हम पर्यावरण मित्र व लोगों के लिए उपकारी पर्यावरण नियम बनाएँगे।

37) हमारे देश में गाड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। इसलिए मोटर व्हीकल नियमों की पुनर्परीक्षा वांछनीय है।

38) देश में शहरीकरण की द्रुत वृद्धि की प्रयोजन के कारण :

- हमारे देश में द्रुत शहरीकरण के साथ-साथ साधारण हाउसिंग व कम खर्च वाले हाउसिंग पर नजर देना ज़रूरी है। प्रत्येक गरीब व्यक्ति के सर पर छत हो इसलिए हमारे पश्चिम बंगाल में एक योजना है जिसका नाम है 'निज गृह निज भूमि' है। हम इसी प्रकार की एक योजना पूरे देश के लोगों के विकास के लिए शुरू करना चाहते हैं। इसके ज़रिए सार्विक रूप से हाउसिंग की समस्या का पूरी तरह से निराकरण होगा।
- वर्तमान के शहरों का द्रुत विकास और नए शहरों के विकास से शहर की अवसंरचना पर दबाव बढ़ता है। हम समग्र रूप से इस चुनौती के लिए यथोचित कदम उठाएँगे।
- शहरों के विकास के लिए और एक समग्र मजबूत मॉडल व शहरों की सुविधाओं का विकेंद्रीकरण पर ध्यान देंगे। शहरी गरीबों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

39) पूरे देश में एक प्रमुख हाईवे अपरिहार्य है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तथा कोहिमा से द्वारका तक 'फोर सिस्टर्स' हाईवे कोरिडोर पर ध्यान देंगे। हम 'फोर सिस्टर्स' परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करेंगे।

40) वर्तमान में, रेलवे का सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे पास 'विज़न 2020' नामक एक अभिनव दस्तावेज है जिसे वर्ष 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था। तकनीकी विकास के जरिए 'विज़न 2020' हमें तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य की ओर ले जाएगा।

41) गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, ब्राह्मणी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सुंदरवन का प्रायद्वीप, केरल के बैक वाटर आदि को शामिल कर, जल परिवहन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यह कॉरिडोर सिर्फ़ माल परिवहन के लिए ही उपयोग में नहीं लाया जाएगा बल्कि सामान्य पर्यटन व हैरिटेज पर्यटन के काम में भी आएगा।

42) हमें गैर-सरकारी व सरकारी भागेदारी वाले व्यवसायों से पर्याप्त लाभ नहीं मिला। इसके लिए हम इस प्रकार के भागेदारी वाले व्यवसायों की पालिसी को अच्छी तरह से पढ़ कर देखेंगे।

43) हमारे इंडियन पेनल कोड व सी पी आर सी के कानून बने थे साम्राज्यवाद शासन के समय। लेकिन समय के साथ सामंजस्य रखते हुए इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इनका संशोधन आवश्यक है। जिससे अपराधमूलक कार्य व महिलाओं पर हो रहे अन्याय बंद हों।

44) भूमि अधिग्रहण नीति के दृष्टिकोण में तुरंत परिवर्तन आवश्यक है। बल पूर्वक कृषि सहित अन्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। सरकारी लैंड बैंक बनाना बहुत जरूरी है। राज्य व केंद्र सरकार के प्रत्येक विभाग की ज़मीन इसमें होनी चाहिए। इन जमीनों को औद्योगिक विकास व लोजिस्टिक हब बनाने के काम में लिया जा सकता है। लेकिन इस विषय पर पारदर्शिता रहनी चाहिए। साथ ही भूमि के उपयोग सम्बंधित नियम भी रहेंगे।

45) हमारे वन कानून को भी बदलना ज़रूरी है। वन में रहनेवाले तथा आदिवासियों के हितों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है।

46) 'सभी के लिए बिजली' हमारा लक्ष्य है। भारत के सभी गांवों में उच्च स्तरीय बिजली पहुँचाना ही हमारा लक्ष्य है।

47) जल्दी ही, हम क्लीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक गैस, कोल बेड मीथेन, गैस फायर्ड ताप विद्युत्, जल शक्ति, शेल गैस व अन्य अप्रचलित शक्तियों की ओर हम विशेष ध्यान देंगे। इसके लिए हमें एक एनर्जी पालिसी की ज़रूरत है।

48) अवसंरचना या बुनियादी ढाँचा (Infrastructure), आधुनिक अर्थनीति का मेरुदंड है। और यह बजट व मूलधन व्यय द्वारा संचालित होता है। (पश्चिम बंगाल ने पिछले सात वर्षों में 8.5 गुना ज्यादा पूँजी व्यय कर के इंफ्रास्ट्रक्चर संपदा का सृजन किया)। इसके द्वारा हमारे देश के आधुनिक अवसंरचना को सहूलियत होगी।

49) हम जानते हैं कि बारिश का पानी सागर में ही जाकर मिलता है। इसके लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पालिसी बनाएँगे।

50) हम देश और विदेश में गए काले धन को सटीक पद्धति से सामने लाएंगे।

51) राज्य व केंद्र की सभी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से सम्मानपूर्वक कार्य कर सकें इस ओर हम ध्यान देंगे।

52) कश्मीर में शांति लौटाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम पूरे देश की आस्था व विश्वास अर्जित करके उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे ।

53) हमें खाद्य वस्तुओं के परिमाण को बढ़ाना होगा जिससे खाद्य, जलावन और औषधि का दुरुपयोग न हो। इसके लिए उचित नियम बनाने होंगे।

54) हम द्रुतता से जी एस टी कौंसिल के माध्यम से जी एस टी प्रणाली में परिवर्तन लायेंगे जिससे छोटी व मझोली संस्थाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके।

55) देश का एक भी गाँव बैंकहीन नहीं रहेगा। आम लोगों की सुविधा के लिए देश के डाकघरों का विस्तार जरूरी है, इसलिए डाकघरों के पुनर्गठन के माध्यम से अर्थनैतिक परिसेवा प्रदान करने के लिए व्यवहार किया जायेगा।

56) हमें एक नई फॉरेन ट्रेड पालिसी लानी चाहिए जिससे निर्यात पर कम शुल्क तथा आयात पर वर्धित शुल्क के जरिए एक सामंजस्य स्थापित हो सके। इस

क्षेत्र में भी हमारी दृष्टि एम एस एम ई तथा श्रम सघन उद्योगों पर रहेगी। हम अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तथा वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन के अंतर्गत विकासशील आर्थिक नीति का भी ध्यान रखेंगे।

57) मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग को विघटित करना एक गलत निर्णय था।सारे देश एवं सभी राज्यों के बहुमुखी एवं सर्वांगीण विकास के लिए, हम भारत के योजना आयोग (Planning Commission) को पुनः स्थापित करेंगे। इसके माध्यम से केंद्र व राज्यों के बीच विचारों का आदान-प्रदान शुरू होगा एवं देश सही दिशा में आगे बढ़ सकेगा।

58) यदि राज्य सरकारों का राज्य के विभाजन संबंधी कोई प्रस्ताव हो तो, हम उसकी विवेचना करेंगे।

59) हमारी विदेश नीति सभी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्वक रूप से मिलजुल कर सह अवस्थान पर निर्भर होनी चाहिए। हमारी कोशिश आपसी मेल मिलाप को बढ़ाने की होगी। विशेष तौर पर सामाजिक आर्थिक व तकनीकी क्षेत्रों में। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' हमारा दर्शन होना चाहिए। The World is one sweet family।

60) सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी प्रासंगिक है। हम समय निर्धारित, एक मास्टर प्लान को सामने रखकर देश में ही आवश्यक यंत्रादि निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया व पालिसी का प्रणयन करना होगा। सुरक्षा से जुड़े लोग व उनके परिवारों को सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा हम सुरक्षा के क्षेत्र में भर्ती के लिए एक विशेष नीति को लाना चाहते हैं।

61) देश के सभी जवानों व उनके परिवारों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक सार्विक परिकल्पना का रूपायन करेंगे।

पश्चिम बंगाल में सुशासन का दृष्टांत

माँ माटी मानुष की सरकार द्वारा
राज्य में साढ़े सात साल में विकास - एक नज़र

- **राज्य की लगभग 10 करोड़ आबादी में से 90 प्रतिशत लोगों ने किसी न किसी सरकारी परिसेवा का लाभ प्राप्त किया है।**
- वर्तमान सरकार के कार्यक्रम मनुष्य के **जन्म से लेकर मृत्यु तक,** हर क्षेत्र में लाभदायक हो रहे हैं।
- शिशु के जन्म के समय **'सबुजश्री'** परियोजनांतर्गत एक मूल्यवान नन्हा पौधा (चारा) - इसके बाद है **'कन्याश्री', 'शिक्षाश्री', 'सबुजसाथी', 'स्वामी विवेकानंद मेरिट-कम-मिन्स स्कालरशिप', 'खाद्यसाथी', 'युवश्री', 'रूपश्री', 'स्वामी विवेकानंद स्वनिर्भर कर्म संस्थान परियोजना', 'सामाजिक सुरक्षा योजना'** जैसी एकगुच्छ परियोजनाएँ और सबके बाद - **'समव्यथी'**।
- **देश में 1 नंबर-**
  - **जीएसडीपी वृद्धि देश में सबसे अधिक**
  - **100 दिवसीय कार्यक्रम, ग्रामीण आवास व ग्रामीण रास्ता निर्माण में देश में सर्वश्रेष्ठ**
  - **कौशल विकास** (Skill Development) **में देश में एक नंबर**
  - **सरकारी कार्य में स्वच्छता व ई-टेंडरिंग में देश में सर्वश्रेष्ठ**
  - **एम एस एम ई** (MSME) **सेक्टर में ऋण मुहैया कराने में देश में सर्वश्रेष्ठ**
  - **'ईज अब डूइंग बिज़नेस' में देश में श्रेष्ठ**
  - **अल्पसंख्यकों के विकास व ऋण प्रदान करने में देश में सर्वश्रेष्ठ**
  - **कृषकों की आय वृद्धि में देश में सर्वश्रेष्ठ (3 गुना आय बढ़ी है)**
- **अग्रणी बंगाल -**
  - **बंगाल का जीवीए** (Gross Value Added) **वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि से 65 प्रतिशत अधिक है**
  - **बंगाल का औद्योगिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से 194 प्रतिशत अधिक है**
  - **बंगाल के परिसेवा क्षेत्र की वृद्धि राष्ट्रीय दर से 26 प्रतिशत अधिक है**
  - **बंगाल की कृषि व कृषि संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 247 प्रतिशत अधिक है**
  - **बंगाल में राजस्व अदायगी बीते साढ़े सात सालों में ढाई गुना बढ़ी है**
  - **राज्य में बेरोजगारी 40 प्रतिशत कम हुई है**

- **बीते साढ़े सात सालों में राज्य सरकार के मूलधन क्षेत्र में 9 गुना खर्च बढ़ा है। सामाजिक क्षेत्र में खर्च बढ़ा है 4 गुना, कृषि व कृषि संबद्ध क्षेत्र में लगभग 7 गुना एवं बुनियादी विकास में लगभग 4 गुना खर्च बढ़ा है।**
- **देश में सबसे अधिक धान, सब्जी, मधु व छोटी मछली का उत्पादन**

- **कृषि व कृषि संबद्ध क्षेत्र**
  - **कृषकों की आय में 3 गुना वृद्धि**
  - खाद्य संबंधी उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा क्रमशः **5 बार 'कृषिकर्मण' पुरस्कार**
  - **30 जनवरी, 2019 से 'कृषक बन्धु' परियोजना** चालू हुई है-राज्य के किसानों को **वर्ष में दो किश्तों में प्रति एकड़ कुल 5 हजार रुपये की मदद।**
  - जिसके पास **एक एकड़ से कम ज़मीन** है, वे भी जमीन की मात्रा के अनुसार **आंशिक मदद (न्यूनतम एक हजार रुपये)** पायेंगे।
  - **18 साल से 60 साल तक के कृषक की मृत्यु होने पर** उसके परिवार को **2 लाख रुपये की मदद**।
  - इसके लिए राज्य सरकार के लगभग **5 हजार करोड़ रुपये खर्च** होंगे।
  - इस परियोजना से प्रदेश के लगभग **72 लाख कृषक लाभान्वित** होंगे।
  - कृषकों के **फसल बीमा के प्रीमियम का सारा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है।** कृषकों को इसके लिए रुपये नहीं देने पड़ते है - इसके लिए सरकार के प्रति वर्ष **700 करोड़ रुपये खर्च होंगे**।
  - कृषकों को धान का न्याय मूल्य उन तक पहुँचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए **चालू किया गया है 'निजे धान दिन, निजे चेक निन' परियोजना**।
  - **कृषि जमीन के लिए खाजना व म्यूटेशन फीस निःशुल्क किया** गया है
  - 2018-19 खरीफ फसल, **धान का न्यूनतम सहायक मूल्य** (2017-2018 खरीफ फसल प्रति क्विंटल 1550/- से) बढ़ाकर प्रति क्विंटल **1750 रुपये किया गया है**।
  - अन्य **फसलों की अभावी बिक्री बंद करने तथा उत्पादित** फसलों के न्याय मूल्य निश्चित करने के लिए एक **विशेष कोष** का गठन किया गया है।
  - **प्राकृतिक विपदा से फसल नष्ट होने से लगभग 66 लाख कृषक परिवारों** को नये सिरे से खेती करने के लिए राज्य के निजी कोष **से लगभग 2 हजार 415 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता** दी गयी है।

- **कृषक बुढ़ापा भत्ता का परिमाण मासिक 750 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये** कर दिया गया है एवं **उपभोक्ताओं की संख्या 66 हजार से बढ़कर 1 लाख हुई है।**
- कुल **963 कस्टम हायरिंग सेंटर** स्थापित किये गये हैं, जहाँ से **न्यूनतम भाड़े पर छोटे व प्रांतिक किसानों को कृषि औजार उपलब्ध** कराये जाते हैं।
- **50 लाख से अधिक 'सॉयल हेल्थ कार्ड'** वितरण किये गये हैं
- दलहन उत्पादन 2.51 गुना, तेल बीज उत्पादन 1.6 गुना, भुट्टा उत्पादन 3.8 गुना, कुल खाद्य सामग्री उत्पादन में 1.24 गुना वृद्धि हुई है। इससे कृषकों में कई गुना अधिक उपार्जन का सुयोग उत्पन्न हुआ है।
- पूरे राज्य में **69 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं। 2011 से पहले यह संख्या मात्र 27 लाख थी।**
- राज्य में 186 **'किसान मंडी'** तैयार किए गए हैं।
- नियमित तौर पर **'माटी उत्सव'** का आयोजन किया जा रहा है।
- **सिंगुर आन्दोलन की स्मृति में मनुमेन्ट** तैयार किया जा रहा है। इस आन्दोलन को स्मरण कर, **प्रति वर्ष 14 सितंबर को सिंगुर दिवस** का पालन किया जाता है।
- नन्दीग्राम कृषक आन्दोलन के शहीदों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए वर्ष 2012 से, **प्रति वर्ष 14 मार्च को 'कृषक दिवस' मनाया जा रहा है।** इस दिन कृषकों को **'कृषक रत्न'** सम्मान प्रदान किया जाता है।
- पूरे राज्य में **2011-2017 साल में प्रदत्त भूमि पट्टों की संख्या 3 लाख 5 हजार** से अधिक है जबकि 2005-11 **के बीच यह संख्या कुल 1 लाख 60 हजार थी।**
- **घर बैठे बैठे आनलाइन** ज़मीन संबंधी विभिन्न परिसेवा जैसे **जमीन पर्चा, म्यूटेशन, कनवर्जन** इत्यादि पाने के लिए नया **'इलेक्ट्रानिक डेलिवरी सर्विस'** चालू की गयी है।
- **उत्तराधिकारी के तौर पर प्राप्त जमीन के म्यूटेशन के क्षेत्र में म्यूटेशन फीस खत्म कर** दी गयी है।
- जिन पंचायतों में अभी भी बैंकिंग परिसेवा नहीं शुरू हुई है, वहाँ राज्य के **कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से बैंकिंग परिसेवा** मुहैया कराने की व्यवस्था की जा रही है।

- **'मौयना माडल'** के माध्यम से तालाबों में रूई, कातला, मृगेल इत्यादि प्रजाति की छोटी मछलियों का पालन कर प्रति हेक्टेयर 12000 किलो मछली का उत्पादन किया जा रहा है।
- **'जल धरो जल भरो' परियोजनांतर्गत 2 लाख 62 हजार से अधिक तालाबों का खनन किया गया है,** जिनका उपयोग मछली पालन के लिए किया जा रहा है।
- **मत्स्यजीवियों को आवास बनाने के लिए दिये जाने वाले अनुदान को 75 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।**
- **उल्लेखनीय है कि राज्य के लगभग 15 हजार से अधिक प्राणी बंधु/प्राणी मित्र/प्राणी सेवी के लिए 1500/-रुपये नियमित पारिश्रमिक सुनिश्चित** किया गया है। इसके साथ ही निर्दिष्ट परिमाण से **अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त उत्साह भत्ता सह प्रति 3 वर्ष के अन्तराल पर 10 प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि** की व्यवस्था की गयी है।
- बतख व **मुर्गी के अंडे उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य से नई विशेष उत्साह परियोजना-2017 शुरू की गई है।**
- **इस परियोजनांतर्गत** अंडा उत्पादक को बतख या **मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए सरकार से अनुदान, मियादी ऋण पर ब्याज में छूट, बिजली बिल पर सहायता व छूट एवं स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस में सरकारी मदद** दी जा रही है।

- **स्वास्थ्य व परिवार कल्याण**
  - **सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज व रोग निदान की व्यवस्था**
  - **'स्वास्थ्य साथी'** परियोजना के माध्यम से **गैर सरकारी अस्पतालों में भी निःशुल्क 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का सुयोग। इस परियोजना के माध्यम से डेढ़ करोड़ परिवार के लगभग साढ़े 7 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। परिणामस्वरूप, राज्य के 75 प्रतिशत लोग स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत पंजीकृत हैं।**
  - **स्वनिर्भर गोष्ठी/आशा कर्मी/आईसीडीएस कर्मी/सिविक वोलंटियर/पंचायत व म्यूनिसपलिटी के निर्वाचित सदस्यगण/भूतपूर्व खिलाड़ी/स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, सर्वशिक्षा मिशन, राज्य के सरकारी कार्यालय व राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों में नियुक्त ठेका**

श्रमिक/ पैरा टीचर, ग्राम पंचायत से संबद्ध होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक चिकित्सक/शिशु शिक्षा केंद्र व मदरसा शिक्षा केंद्र के सम्प्रसारक व सम्प्रसारिका/कलकत्ता हाई कोर्ट के अस्थायी कर्मचारी/ पूर्व पंजीकृत आर.एस.वी.वाई के सुविधाभोगी/परिचारिका, हाकर्स, सेनिटेशन वर्कर्स, परिवहन कर्मीगण, रिक्शा चालक, दुकान के कर्मचारी - ये सभी लोग सपरिवार एवं राज्य के एस.ई.सी.सी. के अनुसार विवेचित परिवार के सदस्यगण अब स्वास्थ्य साथी परियोजना के सुविधाभोगी हैं।

- महिला सशक्तीकरण के अंतर्गत स्वास्थ्य **साथी स्मार्ट कार्ड को परिवार की महिला** सदस्य के नाम से दिया जा रहा है। इस परियोजना का लाभ हितग्राही महिला के परिवार के सदस्यों के अलावा, **उसके माँ व पिता को भी मिलती है**।
- स्वास्थ्य साथी परियोजनांतर्गत चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार के **प्रति वर्ष 925 करोड़ रुपये खर्च होंगे**।
- जिला स्तर पर अत्याधुनिक चिकित्सा परिसेवा उलब्ध कराने के लिए पूरे राज्य में **42 मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण** किया गया है।
- सरकारी अस्पतालों में **28 हजार से भी अधिक शैया** संख्या बढ़ायी गयी है।
- बीते साढ़े सात साल में **8 मेडिकल कालेज चालू किए गए हैं** एवं और **10 मेडिकल कालेजों का निर्माण** कार्य चल रहा है।
- वर्तमान समय में, पूरे राज्य में कुल **301 एसएनएसयू** एव **69 एसएनसीयू है, जबकि वर्ष 2011 से पूर्व राज्य में एक भी एसएनएसयू नहीं था एवं मात्र 6 एसएनसीयू** था।
- **42 क्रिटिकल केयर यूनिट, 26 हाई डिपेन्डेंसी यूनिट, 16 मदर एंड चाइल्ड हब, 116 उचित मूल्य की दवा दुकान एवं 130 उचित मूल्य के डायग्नोस्टिक सेंटर** का निर्माण किया गया है।
- गर्भवती महिलाओं/प्रसूति के लिए राज्य के विभिन्न अंचलों में **12 वेटिंग हट बनाये गये हैं**।
- प्रदेश में 11 हजार से अधिक हेल्थ सब सेन्टर व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुस्वास्थ्य केंद्र के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस बीच, 430 सुस्वास्थ्य केंद्र चालू किये गये हैं।

- **संस्थागत प्रसव वर्ष 2011 से 65 प्रतिशत से बढ़कर 97.5** प्रतिशत हुआ है।
- **शिशु मृत्यु दर** वर्ष 2011 के **32 से कम होकर 25** हुई है।
- **मातृ मृत्यु दर** वर्ष 2011 के **113 से कम होकर 101** हुई है।
- **टीकाकरण** वर्ष 2011 में **80 प्रतिशत से बढ़कर 99 प्रतिशत** हुआ है।

- **शिक्षा व तकनीकी शिक्षा**
  - स्कूली छात्र-छात्राओं को **निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस, जूते, बैग, टेस्ट पेपर्स**
  - सभी स्कूलों में **मिड डे मील**
  - सभी स्कूलों में **पेय जल, लड़कियों के लिए अलग शौचालय**
  - बीते साढ़े सात साल में **लगभग 1 हजार नये प्राथमिक व 6 हजार नये उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना** की गयी है। **लगभग 700 उच्च प्राथमिक स्कूलों को सेकेंडरी एवं 2 हजार से अधिक सेकेंडरी स्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नत किया** गया है।
  - राज्य में **28 नये विश्वविद्यालय व 50 नये कालेज स्थापित किये गये हैं।** इसके अलावा **और 11 नये विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है।**
  - इसके अलावा, **राज्य में हिन्दी माध्यम के 2 कालेज व हावड़ा जिला के आरूपाड़ा में** राज्य के **प्रथम हिन्दी विश्वविद्यालय का निर्माण किया** जा रहा है।
  - **ठाकुरनगर** में नया **हरिचाँद-गुरुचाँद विश्वविद्यालय** का निर्माण हो रहा है एवं कृष्णनगर में **इस विश्वविद्यालय के एक्सटेंशन कैम्पस** का निर्माण किया जा रहा है।
  - **कृष्णनगर** में **कन्याश्री विश्वविद्यालय** बनाया जा रहा है।
  - **राजारहाट के न्यू टाउन** में लगभग 257 करोड़ रुपये की लागत से **आलिया विश्वविद्यालय के नव निर्मित भवन** का निर्माण किया गया है।
  - **पूर्व मेदिनीपुर के महिषादल** में **महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय का निर्माण** किया जा रहा है।

- **डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय** का निर्माण किया गया है - **पूर्वांचल का प्रथम महिला विश्वविद्यालय।**
- सम्प्रति, **प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय का न्यू टाउन कैम्पस चालू हुआ** है। इस नये कैम्पस की स्थापना के लिए राज्य सरकार की तरफ से **निःशुल्क 10 एकड़ जमीन** एवं नये भवन के निर्माण के लिए **लगभग 185 करोड़** राशि दी गई है।
- **यूजीसी द्वारा एम फिल व पी एच डी छात्र-छात्राओं के लिए रिसर्च स्कालरशिप के बंद किये जाने के बाद, राज्य सरकार ने अपने निजी कोष से वित्त आबंटित किया है।**
- **कल्याणी** में राज्य के प्रथम **Indian Institute of Information Technology (IIIT) का निर्माण** किया गया है।
- **फुलिया** में **राज्य के प्रथम Indian Institute of Handloom Technology (IIHT) का निर्माण** किया गया है।
- **हरिनघाटा** में चालू हुआ है **MAKAUT (Maulana Abul Kalam Azad University of Technology)** का नया कैम्पस।
- तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत **188 नया आई.टी.आई व 88 नये पालीटेक्निक कालेजों** की स्थापना हुई है **जबकि वर्ष 2011 से पहले राज्य में मात्र 80 आई टी आई और 65 पालीटेक्निक कालेज थे।**
- **'उत्कर्ष बांग्ला' कर्मसूची के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख युवक-युवतियों कौशल प्रशिक्षण** (skill training) दिया जा रहा है।
- **'उत्कर्ष बांग्ला' परियोजना को यूनाइटेड नेशंस के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। संपूर्ण विश्व की 1140 परियोजनाओं के बीच प्रथम 5** में निर्वाचित।
- **वर्ष 2013, 2014 एवं 2016 में आल इंडिया स्किल कम्पीटीशन में बंगाल को प्रथम स्थान प्राप्त।**

- **पंचायत व ग्राम विकास**
  - **100 दिवसीय कार्य, ग्रामीण आवास व ग्रामीण सड़क परियोजना में बंगाल देश में सर्वश्रेष्ठ**

- **100 दिवसीय कार्य, कुल कार्य दिवस सृजित करने में, प्रत्येक परिवार के लिए श्रम दिवस सृजित करने में एवं कुल खर्च के हिसाब से बंगाल देश में एक नंबर है।**
- बीते साढ़े सात साल में राज्य में **100 दिवसीय कार्य में लगभग 42,126 करोड़ रुपये खर्च कर लगभग कुल 191 करोड़ से भी अधिक श्रम दिवस सृजित किया** गया है।
- ग्राम व शहर में बीते साढ़े सात साल में **कुल 40 लाख घरों का निर्माण किया गया है एवं 26000 किलोमीटर रास्तों का निर्माण व पुनर्निर्माण** किया गया है।
- 100 दिवसीय कार्य, बांग्लार आवास योजना इत्यादि परियोजनाओं से संबद्ध राज्य के **लगभग 25 हजार विलेज रिसोर्स पर्सन के वार्षिक कार्य दिवस को (30 दिन से) बढ़ाकर 50-55 दिन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वे लोग वार्षिक 16 हजार रुपये तक आय कर पायेंगे।**
- '**समव्यथी**' परियोजनांतर्गत पूरे राज्य में **2 लाख लोग उपकृत हुए है**।
- '**वैतरणी**' परियोजनांतर्गत **शमशान व विद्युत चूल्हे का उन्नतीकरण** किया गया है।

- **अल्पसंख्यक विकास**
  - अल्पसंख्यक विकास विभाग का **2010-2011 का बजट 472 करोड़ रुपये से 8 गुना बढ़ाकर साल 2018-19 में 3258 करोड़** रुपये हुआ है।
  - बीते **साढ़े सात साल में,** राज्य में:
    - **2 करोड़ 3 लाख से अधिक अल्पसंख्यक स्कालरशिप दी गयी हैं, जिसका आर्थिक मूल्य 5257 करोड़ रुपये से अधिक है एवं** जो **देश में प्रथम स्थान पर है**।
    - **8 लाख से अधिक अल्पसंख्यक युवक-युवतियों को स्वरोजगार के लिए 1300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया गया है, जो देश में एक नंबर है।**
  - उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य छात्र-छात्राओं की संख्या को कम किए बगैर अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 17 प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी की गयी है।
  - स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन के लिए, पूरे राज्य में 528 **'कर्मतीर्थों'** का निर्माण किया गया है।

- न्यू टाउन में लगभग 20 एकड़ जगह में लगभग 257 करोड़ रुपये की लागत से आलिया विश्वविद्यालय का नया कैम्पस एवं छात्र-छात्राओं के लिए अलग से हास्टल बनाया गया है।
- राजारहाट में 5 एकड़ जमीन पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से 12 मंजिला तीसरा हज कम्पलेक्स मदिना-तुल-हज्जाज का निर्माण किया गया है। यहाँ एक साथ 3 हजार से अधिक हज यात्री रह सकते हैं।
- लगभग साढ़े 4 हजार कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंडरी वाल बनायी गयी है।

- **पिछड़ा वर्ग कल्याण व आदिवासी विकास**
  - पिछड़ा वर्ग कल्याण व आदिवासी विकास विभाग का संयुक्त आबंटित बजट वर्ष 2010-2011 में 566.50 करोड़ रुपये था, जो तीन गुना बढ़कर वर्ष 2018-19 1785 करोड़ रुपये हो गया है।
  - अलग से आदिवासी विकास विभाग का गठन किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री महोदया खुद देख रही हैं।
  - माननीया मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में ट्राइब्स एडवाइजरी कौंसिल व शिड्यूल कास्ट एडवाइजरी कौंसिल का गठन किया गया है एवं नियमित मीटिंग के माध्यम से आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोगों के विभिन्न विकास परियोजनाओं के ज़रिये विकास किया जा रहा है।
  - **'सबुज साथी'** परियोजनांतर्गत क्लास 8 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को कुल एक करोड़ साइकिल प्रदान की गयी है।
  - **'सबुज साथी'** परियोजना यूनाइटेड नेशंस के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए मनोनीत की गई है। समग्र विश्व के 1140 प्रकल्पों में प्रथम 5 में निर्वाचित।
  - विगत साढ़े सात साल में सारे राज्य में **70 लाख छात्र-छात्राओं ने शिक्षाश्री परियोजनांतर्गत सहायता पायी है।**
  - अभी, प्रदेश में प्रति वर्ष 9 लाख **SC/ST/OBC Certificate प्रदान किये जा रहे हैं, जबकि 2011 से पूर्व यह संख्या मात्र ढाई लाख थी।**
  - **SC/ST छात्र-छात्राओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा के लिए देश में कहीं भी पढ़ने के लिए 10 लाख रुपये तथा विदेश में पढ़ाई करने के**

लिए सर्वाधिक 20 लाख रुपये आसान किश्तों पर ऋण के तौर पर दी जा रही है। यह देश में एक माडल के रूप में है।

- **SC/ST छात्र-छात्राओं को ज्वाइंट एन्ट्रेंस कोचिंग** के लिए प्रदेश में 36 केंद्रों की स्थापना की गयी है।
- पूरे राज्य में **अनुसूचित जनजाति वृद्ध पेंशन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाकर डेढ़ लाख किया** गया है।
- बीड़ी पत्ता संग्रहकारी, दरिद्र आदिवासी व अन्य के परिवारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **West Bengal Kendu Leaves Collectors Social Security Scheme, 2015 चालू किया** गया है। **राज्य में 35 हजार से अधिक परिवारों को इस परियोजना में शामिल** किया गया है।
- इस कर्मसूची में,
  - **60 साल की उम्र होने पर डेढ़ लाख रुपये तक**
  - **दुर्घटना जनित मृत्यु होने पर एककालीन डेढ़ लाख रुपये व स्वाभाविक मृत्यु होने पर एककालीन 50 हजार रुपये**
  - **स्थायी अक्षमता के लिए 25 हजार रुपये**
  - **मातृत्वकालीन सहायता के रूप में 6 हजार रुपये**
  - **अस्वस्थ होने पर वार्षिक 25 हजार रुपये**
  - **परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर दाह संस्कार के लिए 3 हजार रुपये की सहायता।**
- **नमःशूद्र व मतुआ सम्प्रदाय** के लोगों की उन्नति के लिए **2 बोर्ड का गठन किया गया है**। इसे लेकर, कुल 22 बोर्डों का गठन किया गया।
- **जाहेर थान के लिए पट्टा एवं उसके चारो तरफ बाउंडरी वाल का निर्माण** किया जा रहा है।
- **राजवंशी व कामतापुरी को सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति दी गयी** है।
- **संथाली भाषा को विशेष मर्यादा देने के लिए WBCS परीक्षा में ऐच्छिक विषय के तौर पर शामिल किया गया है। आलचिकि लिपि में स्कूली पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन** किया जा रहा है।
- **राजवंशी भाषा अकादमी गठन के साथ साथ राजवंशी सांस्कृतिक** विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

- **जंगलमहल विकास**
  - **जंगलमहल में शांति स्थापित** करने के पश्चात, बरकरार है।
  - **राज्य सरकार की आर्थिक मदद** Jangalmahal Action Plan (JAP) कर्मसूची अंतर्गत बाँकुड़ा, झाड़ग्राम, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर व वीरभूम जिले में विकास कार्य अबाध गति से चल रहा है।
  - जंगलमहल इलाके में लगभग 32 हजार हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, **500 करोड़ रुपये की लागत से जलतीर्थ परियोजनांतर्गत चेक डैम व जल संरक्षण टैंक तैयार किये जा रहे हैं।**
  - **जंगलमहल के 33 हजार से अधिक युवक-युवतियों ने** Employment Bank के जरिये **पुलिस सेवा में विभिन्न पदों पर नौकरी प्राप्त** की है।
  - पश्चिमांचल विकास विभाग द्वारा जल संरक्षण, सिंचाई, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, पेय जल व्यवस्था
  - आधारित योजनाओं का अबाध गति से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
  - साथ ही लाख की खेती का उत्पादन बढ़ाकर, इस इलाके के लोगों के लिए रोजगार सृजन किया गया है।
  - बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए बाँकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर जिला में Nutrition Rehabilitation Centre का निर्माण किया गया है।
- **नारी व शिशु विकास एवं समाज कल्याण**
  - **'कन्याश्री'** परियोजनांतर्गत **वार्षिक आय की न्यूनतम सीमा को खत्म कर** दिया गया है। इसके फलस्वरूप **अब सभी कन्याएँ 'कन्याश्री' हैं। पूरे राज्य में 60 लाख से अधिक 'कन्याश्री' हैं।**
  - **के-1 परियोजना में भत्ता परिमान को 750 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया** गया है।
  - **के-3 परियोजनांतर्गत विश्वविद्यालयों में विज्ञान संकाय से पढ़ाई करने वाली छात्राओं को मासिक 2500 रुपये तथा कला/वाणिज्य संकाय से पढ़ाई करने वाली छात्राओं को मासिक 2000 हजार रुपये दिये** जा रहे हैं।
  - **'कन्याश्री' परियोजना ने विश्व के 62 देशों के 552 विभिन्न परियोजनाओं को पछाड़ कर संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च पुरस्कार जीता है।**

- इसके अलावा चालू हुई है नयी '**रूपश्री**' व '**मानविक**' परियोजना:
  - **रूपश्री परियोजना,** सर्वाधिक डेढ़ लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार की **18 वर्षीय युवती को शादी के लिए 25 हजार रुपये एककालीन मदद दी जा रही है।**
  - **'मानविक' परियोजना, 2 लाख उपभोक्ताओं को मासिक 1000 रुपये प्रतिबंधी भत्ता** दिया जा रहा है।

- **खाद्य सुरक्षा कर्मसूची - खाद्य साथी परियोजना**
  - **खाद्य साथी परियोजनांतर्गत राज्य के लगभग 9 करोड़ लोग, 2 रुपये प्रति किलो के दर से (या बाजार दर से आधी कीमत पर) खाद्यान्न पा रहे हैं।** इसके लिए प्रति वर्ष सरकार के **लगभग 5 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।**
  - पूरे राज्य में **डिजिटल राशन कार्ड का काम 100 प्रतिशत पूरा हो गया** है।

- **चाय बगान: - चाय बगान में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएँ की हैं -**
  - अल्प व दीर्घ मियादी नीति निर्धारण के लिए '**ग्रुप आफ मिनिस्टर्स**' का गठन किया गया है।
  - **दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी व अलीपुरद्वार जिले के लिए, जिला शासक के नेतृत्व में विशेष टास्क फोर्स का गठन** किया गया है।
  - **चाय बगान के कर्मचारियों के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपये का वेलफेयर फंड का गठन** किया गया है।
  - **FAWLOI (Financial Assistance to the Workers in Locked-out Industrial Units)** परियोजनांतर्गत **4 हजार से अधिक चाय श्रमिक 1500/- रुपये मासिक भत्ता पा रहे हैं। 2011 से पूर्व यह राशि प्रतिमाह मात्र 500 रुपये थी।**
  - इस परियोजना में विशेष नीतिगत परिवर्तन कर चाय बंगान के बंद होने पर **पूर्ववर्ती एक साल की जगह 3 महीने में ही सुविधा मुहैया करायी जाती है।**
  - चाय बगान के कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी संशोधन व निर्धारण के लिए **Minimum Wages Advisory Committee** का गठन किया गया है।

- राज्य सरकार के हस्तक्षेप से चाय बगान में कार्यरत **श्रमिक की दैनिक मजदूरी वर्ष 2011 में मात्र 67 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 176 रुपये किया गया है- यह लगभग 3 गुना वृद्धि है**।
- राज्य सरकार के हस्तक्षेप से चाय बगान में कार्यरत श्रमिक का **मासिक कर्मचारी का वेतन, न्यूनतम मजदूरी संशोधन व निर्धारण नहीं होने तक, अंतरिम तौर 18 प्रतिशत** की वृद्धि की गयी है।
- चाय बगान के कर्मचारी के प्रत्येक **परिवार को 2 रुपये प्रति किलो के दर से प्रत्येक मास में 35 किलो खाद्य सामग्री** दी जा रही है।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए चाय बगानों के मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा व ग्रामीण रोजगार सेस को माफ किया गया है।
- चाय बगानों में निःशुल्क बिजली व जलापूर्ति की जा रही है। बिजली बिल नहीं चुका पाने पर काटे गये बिजली कनेक्शनों को फिर से चालू किया गया है।

- **उद्योग**
  - सम्प्रति, अपार सफलता के साथ बंगाल ग्लोबल **बिजनेस समिट-2019 का आयोजन हुआ है।**
  - **इसमें 35 देशों समेत, भारतवर्ष के कई हजार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया**।
  - अधिवेशन के दौरान **85 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए है। 2 लाख 84 हजार 288 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आये हैं**।
  - इसके परिणामस्वरूप, आगामी दिनों में 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
  - इससे पूर्व 4 सम्मेलनों में **लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला था, जिसमें से 50 प्रतिशत क्रियान्वयन के पथ पर है**।
  - सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में और अधिक रोजगार वृद्धि लक्ष्य के अंतर्गत राजारहाट में नया **'बंगाल सिलिकन वैली हब'** का गठन किया गया है। **इसके लिए पहले 100 एकड़ जमीन आबंटित की गयी थी लेकिन बढ़ती माँग को देखते हुए, फिर 100 एकड़ जमीन आबंटित की गई है**।
  - भारी उद्योग के लिए **8 नये इंडस्ट्रियल पार्कों** का निर्माण किया गया है।
  - **16 आई टी पार्क** चालू किए गए हैं।

- **न्यूटाउन** में देश के सबसे बड़े, **'विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेन्टर' का निर्माण किया गया है।**
- **ताजपुर** में एक **बड़े बंदरगाह का निर्माण प्रकल्प शुरू किया गया है।**
- **अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरीडोर परियोजनांतर्गत रघुनाथपुर में 2600 एकड़ में एकीकृत उत्पादन केंद्र व शिल्प क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है।** इसके क्रियान्वित होने पर बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा।
- **गंगासागर** में बड़े बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है- **'भोर सागर'।**
- **बानतला लेदर कॉम्पलेक्स को, विश्व के सबसे बड़े लेदर कॉम्पलेक्स के तौर पर, विकसित किया जा रहा है।** इस राज्य के अलावा, अन्य राज्यों के चमड़ा व्यवसायी यहाँ आ रहे हैं। इसी बीच **कानपुर** व **चेन्नई के अनेक चमड़ा व्यापारियों को यहाँ जमीन दी गयी है।** और भी अनेक व्यवसायियों को यहाँ जमीन दी जायेगी।
- वर्ष 2018 में पहाड़ी इलाके में पहली बार सफलतापूर्वक हिल **बिज़ेनस समिट का आयोजन हुआ है।**
- **वीरभूम** जिला के **देउचा- पाँचामी व देवानगंज-हरिनसिंघा इलाका में देश में सबसे बड़ी कोयला खान का निर्माण किया जा रहा है।** इसके फलस्वरूप, आगामी दिनों में यहाँ के अनेकों युवकों को रोजगार मिलेगा। यह वृहत परियोजना वीरभूम जिला तथा राज्य के औद्योगिक संभावना को और अधिक उज्ज्वल करेगी।
- **सूक्ष्म, मझोले** व **छोटे उद्योगों के लिए बैंक ऋण मुहैया कराने में बंगाल देश में सर्वश्रेष्ठ है।**

- **लोक निर्माण विभाग व परिवहन**
  - **आबंटित बजट के अलावा, लगभग 18 हजार करोड़ रुपये बुनियादी विकास के लिए आबंटित किए गए है एवं ओवर ब्रिज, पेय जल, सड़क व सेतु निर्माण समेत और अन्य कार्य किए जा रहे** हैं।
  - लगभग **3200 करोड़ रुपये की लागत से पूर्व मेदिनीपुर के मेछोग्राम से मुर्शिदाबाद के मोड़ग्राम तक लगभग 270 किलोमीटर वाले North-South Road Corridor का विकास कार्य किया जा रहा है।** इसके पूरा होने पर **उत्तर बंगाल व दक्षिण बंगाल के बीच NH-34 के अलावा एक और वैकल्पिक सड़क व्यवस्था** तैयार हो जायेगी।

- **भूटान-बांग्लादेश संयोगकारी एशियन हाई वे-48 (Asian Highway-48) का निर्माण किया जा रहा** है।
- **नेपाल-बांग्लादेश संयोगकारी एशियन हाई वे-2 (Asian Highway-2) का निर्माण किया जा रहा** है।
- केशियरी व नयाग्राम ब्लाक के खड़गपुर-केशियरी रास्ता व नयाग्राम-धुमसाईं रास्ता के बीच **सुबर्णरेखा नदी के ऊपर 170 करोड़ रुपये की लागत से 'जंगलकन्या' सेतु का निर्माण किया गया है**।
- **आमकला में कंसावती नदी के ऊपर 'लालगढ़' सेतु का निर्माण किया** गया है।
- **कलकत्ता में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर 'सौजन्य', ओपन एयर थियेटर 'उत्तीर्ण' चालू किया गया है।** इसके अलावा, **2400 सीटों वाले प्रेक्षागृह 'धनधान्य' का निर्माण कार्य चल रहा** है।
- **अण्डाल में काजी नजरुल इस्लाम एय़रपोर्ट** का निर्माण के बाद हवाई सेवा शुरू हुई है। यह हमारे **देश का पहला गैर सरकारी कंपनी द्वारा निर्मित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है**।
- **पानागढ़ में 6 लेन बाई पास** का निर्माण किया गया है।
- लगभग 225 करोड़ रुपये की लागत से नामखाना के पास **NH-117** राष्ट्रीय सड़क **हतनिया-दोआनीया नदी पर सेतु का निर्माण** किया गया है।
- **बाटानगर-जिंजिराबाजार** में **'सम्प्रीति' ओवरब्रिज** एवं गार्डेनरीच-**कमालगाछी ओवरब्रिज** का निर्माण किया गया है।
- नया **माझेरहाट ओवरब्रिज का निर्माण किया** जा रहा है।
- **मुड़ीगंगा नदी के उपर एक लोहा पुल बनाने का निर्णय** लिया गया है।
- **'Safe Drive Save Life'** कर्मसूची का क्रियान्वयन किया गया है, इसके फलस्वरूप दुर्घटना व इससे होने वाली मृत्यु की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
- **'गतिधारा'** परियोजनांतर्गत पूरे राज्य में **24 हजार से अधिक युवक-युवतियाँ गाड़ी खरीदने के लिए ऋण पाकर, आत्मनिर्भर** हुई है।
- **असंख्य नये बस, इलेक्ट्रिक बस, जलयान, महिलाओं द्वारा चालित 'पिंक टैक्सी' चालू किया** गया है।

- **विद्युत व गैर - पारम्परिक ऊर्जा**
  - राज्य में लोडशेडिंग अब इतिहास बन गया है।

- लगभग 100 प्रतिशत घरों में बिजली पहुँच रही है।
- वर्ष 2011 में राज्य में जहाँ मात्र 2 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता था, वहीं अब लगभग 130 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। आगामी एक साल में सौर ऊर्जा उत्पादन 100 मेगावाट और बढ़ेगा।
- राज्य के लगभग डेढ़ हजार स्कूलों में प्रत्येक स्कूल में 10 किलोवाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है।
- दीघा के समीप दादनपत्रबार में 200 वाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता संपन्न सोलर ट्री लगाने का काम चल रहा है।

- **सिंचाई**
  - **निम्न दामोदर अववाहिका (Lower Damodar Basin) में सिंचाई व बाढ़ के नियंत्रण व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए 2768 करोड़ रुपये की एक वृहत परियोजना ली गयी है।** इस परियोजना के क्रियान्वित होने से **बाँकुड़ा, वर्धमान, हुगली व हावड़ा -इन 4 जिलों के 30 लाख लोग उपकृत होंगे।**
  - **आरामबाग महकमा में बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से 40 करोड़ रुपये का आरामबाग मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है।** इस परियोजनांतर्गत लगभग 54 किलोमीटर वाले नाला का मरम्मत किया जायेगा। इस परियोजना के क्रियान्वित होने से **आरामबाग, खानाकुल-1 व खानाकुल-2 ब्लाक के विस्तृत इलाके उपकृत होंगे।**
  - **लगभग 650 करोड़ रुपये की लागत से केलेघाई-कपालेश्वरी-बागाई खाल की मरम्मत कार्य पूरा किया गया है।** इसके फलस्वरूप, **पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर व झाड़ग्राम जिले के 14 ब्लाकों के लगभग 4 लाख लोग उपकृत हुए है।**
  - **434 करोड़ रुपये का 'कान्दी मास्टर प्लान' लगभग** पूरा होने के कगार पर है। इसके पूरा होने पर कान्दी इलाका समेत जिले के **लगभग 5 लाख लोग लाभान्वित होंगे।**
  - पश्चिम मेदिनीपुर जिला के घाटाल इलाके में बाढ़ नियंत्रण के लिए कुल **2 हजार करोड़ रुपये का 'घाटाल मास्टर प्लान' तैयार किया गया है।** इसके क्रियान्वित होने पर इस विस्तृत अंचल के **कुल 17 लाख लोग प्रति वर्ष होने वाली बाढ़जनित समस्याओं से मुक्ति पायेंगे।**

- **कुल 114 करोड़ रुपये की लागत से मेदिनीपुर के मुख्य नाले का मरम्मत कार्य जारी है।**

- **जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी**
  - राज्य के **प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल** की आपूर्ति के लिए अनेक परियोजनाओं के अंतर्गत काम चल रहा है। बीते साढ़े सात में इस उद्देश्य के अंतर्गत कुल **12 हजार करोड़ रुपये के परियोजनाओं को शुरू किया** गया है।
  - मई, **2011 में राज्य के मात्र 38 प्रतिशत लोग नलवाहित** पेयजल पाते थे, **जो अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।** चालू **कार्यों के शेष होने पर राज्य के कुल 75 प्रतिशत लोगों को नलवाहित शुद्ध पेयजल मिलेगा।**
  - राज्य के **पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना व बाँकुड़ा जिले के लगभग 16 लाख आर्सेनिक व अन्य प्रकार के प्रदूषण प्रभावित लोगों के पास नलवाहित शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए 2300 करोड़ रुपये का राज्य का वृहतम पेयजल परियोजना (West Bengal Drinking Water Sector Improvement Project) शुरू की गयी** है।
    - परियोजना के माध्यम से इस पूरे अंचल में **रातदिन 24 घंटा दैनिक हर व्यक्ति को 70 लीटर पेयजल की आपूर्ति** की जायेगी।
    - सम्पूर्ण परियोजना का पर्यवेक्षण अत्याधुनिक प्रयुक्ति के माध्यम से किया जायेगा।
    - इसके फलस्वरूप जिला, ब्लाक व ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल आपूर्ति दुरुस्त होगी।
  - लगभग **1200 करोड़ रुपये का 'जाईका' जल परियोजना का कार्य आरम्भ किया गया है।** यह राज्य का अन्यतम वृहत पेयजल आपूर्ति परियोजना है। इसके फलस्वरूप **पुरुलिया जिला के 9 ब्लाकों के 8 लाख लोग उपकृत होंगे।**
  - फलता-मथुरापुर अंचल में जलापूर्ति के लिए **लगभग 1333 करोड़ रुपये की एक मेगा परियोजना शुरू की गयी है।**

- **वन व पर्यटन -**
  - **'सबुजश्री'** परियोजनांतर्गत राज्य में **24 लाख शिशुओं को मूल्यवान नन्हा पौधा (चारा) दिया गया है।**
  - पूरे **राज्य में होम स्टे टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को आय उपार्जन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा** है। इस संबंध में **सरकार ने**

एक नीति बनाई है एवं होम स्टे को स्पेशल इन्सेन्टिव दिया जा रहा है।

- **पर्यटन विभाग के समस्त टूरिस्ट लॉज को नये रूप में तैयार किया जा रहा है**।
- **पहाड़ से सागर-** नयी-नयी परियोजनाओं के माध्यम से **पर्यटन केंद्रों का बुनियादी विकास कर, और आकर्षणीय बनाया जा रहा** है।
- **गाजोलडोबा** में तैयार किया जा रहा है **इको-टूरिज्म परियोजना - 'भोरेर आलो'**
- दार्जिलिंग जाने के रास्ते में **सिलिगुड़ी से मात्र 8 किलोमीटर दूर, उत्तर बंगाल में वन्यश्री पार्क - 'बंगाल सफारी' बनाया गया** है।
- **झड़खाली में विश्व के प्रथम मैनग्रोव अरण्य चिड़ियाखाना में व्याघ्र सुन्दरी** एवं **एक इको टूरिज्म परियोजना 'झड़'** को तैयार किया गया है।
- **काँथी से दीघा तक मेरिन ड्राइव बनाया** जा रहा है।
- **बोलपुर में राँगा बितान** पर्यटन केंद्र में सभी सुविधाओं समेत 10 कॉटेजों का निर्माण किया गया है।
- **तारापीठ मंदिर, पाथरचापुरीर दाता बाबा (साहेब) की मजार** इत्यादि का विकास किया गया है।
- **लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से बोलपुर खोआई के किनारे बाउल बितान** का निर्माण किया जा रहा है।
- **कंकालीतला मंदिर व उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्य किया जा रहा है**।
- **बलागढ़ सबुजद्वीप में इको टूरिज्म परियोजना का निर्माण किया जा रहा** है।
- **झाड़ग्राम राजबाड़ी की मरम्मत** सह एकाधिक कॉटेजों का निर्माण किया जा रहा है।
- **सागर में 'ढेउ सागर' व 'रूप सागर',** समुद्र किनारों पर विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- **तारकेश्वर, तारापीठ-रामपुरहाट, बक्रेश्वर, फुरफुरा शरीफ एवं पाथरचापुरी इलाके में विकास बोर्डों के गठन के** माध्यम से कार्य अबाध गति से चल रहा है।
- **दक्षिणेश्वर काली मंदिर में प्रकाश सज्जा की गई। यहाँ दक्षिणेश्वर रानी रासमणि स्काईवाक का निर्माण किया** गया है।

- **श्रम**
  - राज्य में असंगठित उद्योग व स्वनियुक्ति क्षेत्र (जैसे कृषि, निर्माण उद्योग, परिवहन, बीड़ी उद्योग इत्यादि) से संबद्ध श्रमिक एवं उसके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए **'सामाजिक सुरक्षा योजना'** चालू की गयी है।
  - इस योजना में पंजीकृत **श्रमिक द्वारा 25 रुपये जमा किये जाने पर सरकार उनके खाते में 30 रुपये जमा करेगी। राज्य सरकार जमा राशि पर वार्षिक ब्याज देगी।**
  - इस योजना में पंजीकृत उपभोक्ता एवं उनके परिवार के सदस्यों को निम्न सुविधाएँ मिलती है:
    - **60 वर्ष की आयु होने पर या उससे पहले मृत्यु होने पर, ब्याज समेत मूलधन को लौटाया जाता है।**
    - **स्वाभाविक मृत्यु होने पर 50 हजार तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति दी जाती है।**
    - **अंग हानि होने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति।**
    - **इलाज के लिए वार्षिक 20 हजार रुपये तक एवं आपरेशन के लिए वार्षिक 60 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।**
    - **बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए वार्षिक 4 हजार से 30 हजार रुपये तक भत्ता दिया जाता है।**
    - **एक परिवार की 2 लड़कियों को, अविवाहिता रहकर स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने तक, 25 हजार रुपये का एककालीन अनुदान दिया जाता है।**
  - इस योजनांतर्गत पूरे राज्य में **92 लाख से अधिक असंगठित क्षेत्र के मजदूर/कर्मचारी पंजीकृत हुए है।** अभी तक लगभग 24 लाख उपभोक्ता, कुल 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त किये हैं। **यह केंद्र सरकार की असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजना की तुलना में अधिक बेहतर** है।
  - विगत साढ़े सात साल में, राज्य में **1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इस दौरान लगभग 144 करोड़ कार्य दिवस का सृजन हुआ है।** इसके फलस्वरूप, **विगत 3 साल में राज्य में बेरोजगारी लगभग 40 प्रतिशत कम हुई है।**

- राज्य के **कान्ट्रेक्ट/अनुबंधन/ठेका/दैनिक मजदूरी करने वाले कर्मचारियों को कार्य सुरक्षा देने के लिए उनकी नौकरी की अवधि 60 साल तक सुनिश्चित की गयी है**।

- **सूचना व संस्कृति**
  - राज्य में **लगभग 2 लाख लोक कलाकारों को लोक प्रसार परियोजना में शामिल किया गया है**। ये लोग मासिक पेंशन अथवा रिटेनर फ़ी पा रहे हैं।
  - **पत्रकार बंधुओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 'मावोई' चालू की गयी** है।
  - राज्य के **वरिष्ठ पत्रकारों के लिए एक नयी पेंशन स्कीम चालू की गयी है**।
- **आवासन**
  - **कामकाजी महिलाओं के लिए कोलकाता में 5 हास्टल** बनाये गये हैं। इनका नाम रखा गया है **'कर्मांजलि'**।
  - रोगियों के आत्मीय परिजनों के रात्रि निवास के सुविधार्थ कोलकाता जिले के **नीलरतन सरकार मेडिकल कालेज एवं कोलकाता मेडिकल कालेज** अस्पताल **में एक-एक 'नाइट शेल्टर' का निर्माण किया गया है**। इसके अलावा, **कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कालेज व अस्पताल** में भी एक **'नाइट शेल्टर' का निर्माण** कार्य चल रहा है।
  - **रानीगंज कोयला खान इलाका तथा दुर्गापुर** व **आसनसोल महकमा के विस्तृत अंचल के कुल 45 हजार लोगों के पुनर्वास के लिए जामुड़िया में विशाल आवासन प्रकल्प तैयार किया जा रहा** है।
  - **कुल 68 'पथसाथी'** चालू किये गये हैं। कैनिंग- 2 में एवं सागर में और 2 पथसाथी के निर्माण का काम चल रहा है।
- **खेल व युवा कल्याण -**
  - उत्तर बंग उत्सव, **जंगलमहल कप, राँगामाटी खेल उत्सव, सुन्दरवन कप, कूचबिहार कप खेल प्रतियोगिता, हिमल तराई डुअर्स खेल प्रतियोगिता का नियमित रूप से आयोजन किया** जा रहा है।
  - जलपाईगुड़ी के **'विश्व बांग्ला क्रीड़ांगन'** को नये रूप में सजाया गया है।
  - संपूर्णरूप से सुसज्जित विवेकानंद युवभारती क्रीड़ांगन में अंडर-17 फीफ़ा

विश्व कप का सफल आयोजन किया गया है। एक ही जगह पर क्वाटर फाइनल, सेमी फाइनल एवं फाइनल सह अंतरराष्ट्रीय मानकों के 11 मैचों के आयोजन का उदाहरण इतिहास में अभूतपूर्व है।

- AIFF के सहयोग से **राजारहाट में फुटबाल का** National Centre of Excellence तैयार किया जा रहा है।
- **बारासात स्टेडियम के मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपये प्रदान** किये गये हैं।
- झाड़ग्राम स्टेडियम व **झाड़ग्राम स्पोर्ट्स अकादमी** को नये रूप में तैयार किया जा रहा है।

- **कानून-श्रृंखला व प्रशासनिक सुधार**
  - **जंगल महल व पहाड़ समेत पूरे राज्य में शांति बरकरार है।**
  - **कम्यूनिटी पुलिसिंग** के ज़रिये आम लोगों के साथ संपर्क साधकर, शांति श्रृंखला व साम्प्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखा गया है।
  - **बारासात व बशीरहाट को नये पुलिस जिले का दर्जा** दिया गया है।
  - **अलीपुरद्वार, कलिम्पोंग, झाड़ग्राम व पश्चिम बर्धमान** में नये जिले का गठन किया गया है।
  - **मालदा व मेदिनीपुर में नया विभागीय कमिश्नर** का गठन किया गया है।
  - **मिरिक, मानबाजार व झालदा में नया महकमा स्थापन** किया गया है।
  - **काकद्वीप, डायमंड हार्बर व बारुईपुर में नये पुलिस जिला** का गठन किया गया है।
  - **विधाननगर, बैरकपुर, चंदननगर, हावड़ा, सिलिगुड़ी व आसनसोल-दुर्गापुर में पुलिस कमिश्नरेट** का गठन किया गया है।
  - **पूरे राज्य में 128 नये पुलिस स्टेशन** बनाये गये हैं।
  - **साइबर अपराध कम करने के लिए पूरे राज्य में 25 साइबर थानों का निर्माण किया गया है।**
  - **बारुईपुर** में एक नया करेक्शनल होम (सुधार गृह) बनाया गया है।

हम भारतवर्ष में एकनायकवाद या तानाशाही नहीं चाहते हैं। सभी के हितों के लिए गणतंत्र की प्रतिष्ठा करनी होगी। आइये, देश को दूषित परिवेश तथा तानाशाही मनोभाव से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हों। स्वाधीन होकर भी, मोदी जी व बीजेपी के शासन में आज हम पराधीन हैं।

2019 में शपथ लें
तृणमूल कांग्रेस को वोट दें।
और नहीं दरकार
दिल्ली में बीजेपी की सरकार।

आसन्न १७वीं लोकसभा निर्वाचन में
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थियों को
इस चिह्न पर

वोट देकर विजयी बनायें

सुब्रत बक्शी, साधारण सचिव व पार्थ चट्टोपाध्याय, महासचिव,
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रचारित व फोटो स्कैन ग्राफिक्स प्रा. लि. कलकत्ता-७०००१४ द्वारा मुद्रित